



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत) [संख्या-14

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग—अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग—अलग खण्ड द्वारा संकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	₹0
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	399—481	1600
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	119—122	1500
भाग 2—आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय राजकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के चबूत्रण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़—पत्र, नगर प्रशारान, नोटीफाइल एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अध्यक्ष जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाधन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—विल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	01—13	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	281	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़—पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

17 मार्च, 2023 ई०

संख्या 371 / VII-3-23 / 41—एम०एस०एम०ई० / 2016—राज्य में स्टार्ट—अप इकोरिस्टम विकासित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्टेक—होल्डर्स के साथ व्यापक विवाद—विमर्श के उपरांत कार्यालय ज्ञाप संख्या 403(1) / VII-2-18 / 41—एम०एस०एम०ई० / 2016 दिनांक 22.02.2018 द्वारा प्रख्यापित स्टार्टअप नीति को प्रतद्वारा अतिक्रमित करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी होटल (एनरीआर) से निकटता, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु परिस्थितियों के साथ, उत्तराखण्ड को खाली और कृषि, यात्रा और पर्यटन, शिक्षा, फार्मास्युटिकल वेलनेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मरीन लर्निंग, बिग डेटा, ड्रोन, रोबोटिक्स आदि होटों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए सामरिक हब के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से राज्य की अनुकूल नीतियों, व्यवसाय के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, भजबूत बुनियादी ढांचा व राज्य को देश में स्टार्टप्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये “उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2023” (संलग्नक) प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना संख्या: ३७१/VII-३-२३/४१-एम०एस०एम०ई०/२०१६, दिनांक १७ मार्च, २०२३

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, २०२३

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना

लिंगिका के सूची

पृष्ठमूर्मि	405-406
उद्देश्य	407
दृष्टि	407
लक्ष्य	407
नीति की वैधता	407
1. परिमाण	407
1.1 इकाई का विधिक अस्तित्व	407
1.2 स्टार्टअप	408
1.3 ग्रास रुट इनोवेशन या इनोवेशन/ग्रामीण प्रभाव के साथ स्टार्टअप	408-409
1.4 असंयत प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप	409-410
1.5 महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप	410
1.6 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा स्थापित स्टार्टअप	410
1.7 छात्र उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप	410
1.8 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप	410-411
1.9 टर्नओवर	411
1.10 स्टार्टअप के धरण	411
1.11 नवाचार/नयोनेष	411
1.12 इन्क्यूबेशन सेंटर या इनक्यूबेटर	411-412
1.13 मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर	412
1.14 लोड इन्क्यूबेटर	412-413
1.15 मेन्टर्स	413
1.16 विषय विशेषज्ञ	413
1.17 राज्य सरकार	413
1.18 राज्य सरकार की अभिकरण (एजेंसिया)	413
1.19 अकादमी संस्थान	413
1.20 एक्सलरेटर	413
1.21 एंजेल नेटवर्क	413-414
1.22 उद्यम पूँजी (विवर केपिटल)	414
1.23 चत्तराखण्ड स्टार्टअप कार्डिसिल	414

1.24	राज्य नोखल एजेंसी	414
1.25	उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रकोष्ठ (सेल)	414
1.26	प्रोत्साहन की मान्यता और संवितरण के लिए टास्क फोर्स या समिति	414
1.27	सीमित खण्ड	414-415
2.	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन	415
2.1	मासिक भत्ता	415
2.2	सीड फण्ड	415
2.3	बैंकिंग संपदा अधिकार	415-416
2.4	एमएसएमई नीति के अधीन प्रोत्साहन	416
2.5	प्री-इन्व्यूबेशन सपोर्ट	417
2.6	इन्व्यूबेशन सपोर्ट	417
2.7	औद्योगिक क्षेत्र/आईटी पार्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि का प्राप्तधान	417
2.8	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर	417-418
2.9	पायलट परियोजनायें	418
2.10	एक्सलैरेशन प्रोग्राम	418
2.11	बाहरी फण्डिंग तक पहुंच	418
2.12	ईज ऑफ ड्रुइंग विजनेस	419
2.13	लोक अधिप्राप्ति	419-420
2.14	साझा सुविधाओं तक पहुंच	420
2.15	नियन्त्रण सेवाएं	420
2.16	कुशल मानव संसाधन	420
2.17	मुद्दों या शिकायतों का समाधान	420
2.18	नीतियों और योजनाओं पर सार्वजनिक परामर्श	420
3.	इन्व्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहन	421
3.1	लीड इन्व्यूबेटर	421
3.2	इन्व्यूबेशन केंद्रों के लिए पूर्जीगत अनुदान	421
3.3	इन्व्यूबेशन केंद्रों के लिए प्रदालन अनुदान	421
3.4	शैक्षणिक संस्थानों में इन्व्यूबेशन सेंटर	421-422

4.	शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देना.....	422
4.1	उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई-सेल).....	422
4.2	छात्र स्टार्टअप उद्यमी.....	423
4.3	उद्यमिता पर पाठ्यक्रम.....	423
4.4	व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) को पाठ्यक्रम में शामिल करना.....	423
4.5	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण.....	423
4.6	स्टार्टअप के चलाहकार के रूप में संकाय.....	424
4.7	उद्योग और शिक्षा के बीच साझेदारी.....	424
4.8	शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार का व्यावस्थायीकरण.....	424
5.	सामान्य प्रावधान.....	424
5.1	संस्थागत समर्थन.....	424-425
5.2	फैब लैब या मेकर्स लैब या प्रोटोटाइप लैब.....	425
5.3	फ्लैगशिप कार्यक्रम.....	426
5.4	संवेदीकरण कार्यक्रम.....	426
5.5	फंडस ऑफ फंडस या वैचर फंड.....	426-426
5.6	ईंजेल नेटवर्क की स्थापना.....	426
5.7	राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ.....	426-427
5.8	हैकथॉन या आइडिया चैलेंज.....	427
5.9	महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना.....	427
5.10	क्षमता निर्माण कार्यक्रम.....	427
5.11	जिला नवाचार परिषद.....	427-428
5.12	जिला नवाचार कार्यक्रम.....	428
5.13	बाजार में पहुंच के लिए कॉर्पोरेट इनोवेशन प्रोग्राम (सीआईपी).....	428
5.14	नीति की समीक्षा.....	429
5.15	इस नीति के अधीन प्रोत्साहन और लाभों की अनुमन्यता.....	429

पृष्ठशुमि:

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार भारत विश्व में 12-15 प्रतिशत तक की रिधि वार्षिक वृद्धि के साथ अग्रणी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दहलीज पर है। वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022 की अवधि में देश में 14,000 स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की गयी है और वर्तमान में 70,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। इनमें से लगभग 8,900 - 9,300 प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप हैं, अकेले वर्ष 2021-22 में 1300 नए तकनीकी स्टार्टअप जनित हो रहे हैं। वर्ष 2011 में देश का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप का जन्म होने से लेकर वर्ष 2022 तक भारत में यूनिकॉर्न का शतक पूरा हो गया है। यह भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक दीर्घकालिक और घटनाओं से भरी हुई यात्रा रही है। विश्व रत्न पर स्टार्टअप्स में धन जुटाने और निवेश शिखर पर है। वर्ष 2022 के प्रारम्भ से जुलाई 2022 तक, भारतीय में 19 नए यूनिकॉर्न की शुरुआत हो चुकी है और अब तक यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाले भारतीय टेक स्टार्टअप्स की कल संख्या 105 हो गई है। वित्त पोषण एवं मूल्यांकन गतिविधियों में वृद्धि के साथ, डेकाकोर्न सूची में स्टार्टअप्स की संख्या भी पूरे देश में बढ़ रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से निकटता, भौमिक संसाधनों से समृद्ध अनन्य जलवायु परिस्थितियों के साथ, उत्तराखण्ड को खाद्य और कृषि, यात्रा और पर्यटन, शिक्षा, फार्मास्युटिकल, वैलनेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, सास, ड्रोन, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए रणनीतिक हथ माना जा सकता है। राज्य की अनुकूल नीतियों, व्यवसाय के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, मजबूत युनियादी ढांचा, राज्य को देश में स्टार्टअप्स के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाता है। जून 2022 के अंत तक उत्तराखण्ड राज्य में 700 से अधिक स्टार्टअप्स राखायित हो चुके हैं, जिसकी वर्ष 2018 के अंत तक संख्या मात्र 100 थी। उत्तराखण्ड सरकार के केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप 2022 की पहली तिमाही के अंत तक राज्य के लगभग तेरह (13) स्टार्टअप उल्लेखनीय एंजेल निवेशकों, उद्यम पूँजी फंडों और अन्य निजी निवेशकों से धन जुटाने में सफल रहे हैं। वर्ष 2022 के मध्य तक, राज्य 11 इन्वेस्टर्स नेटर्स में 55,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को इन्वेस्टर्स क्षेत्र में जोड़ने में सक्षम हुआ है, जिसमें स्टार्टअप को तकनीकी और साझा सेवाएं प्रदान करने के लिए 190 से अधिक पंजीकृत सलाहकार, 20 से अधिक एंजेल निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट 13 भागीदार संगठनों के साथ ऑन-बोर्ड हुए हैं।

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में, उत्तराखण्ड को "एसपायरिंग लीडर" और "नियामक धैर्यिन" के रूप में मान्यता दी गई थी। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति की धोषणा के बाद किए गए रणनीतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए इसे "एक संस्थागत धैर्यिन" और "एक क्षमता निर्माण पायनीयर" के रूप में मान्यता दी गई। वर्ष 2021 में स्टार्टअप इंडिया और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा धोषित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखण्ड को "लीडर" के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स पर केंद्रित रणनीतिक पहलों पर उत्तराखण्ड सरकार को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए वर्ष 2020 में स्टार्टअप, इनोवेशन और एंट्रप्रेन्योरशिप पर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह भी बनाया है। स्टार्टअप उत्तराखण्ड में बीस (20) से अधिक विशेष कार्यक्रम हैं, जो इच्छुक उद्यमियों, इन्वेस्टरों, निवेशकों, महिला उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों और राज्य भर के अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारक (प्लेयर्स) के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, सलाह और सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार नवोन्मेषी विचारों की पहचान और मान्यता के लिए स्टार्टअप बूट कैप, ग्रैंड चैलेंज, हैकथर्न आदि

का आयोजन करती है। राज्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर यात्राओं का भी आयोजन करता है।

वर्तमान प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट है कि स्टार्टअप दुनिया भर में नवाचारों का केंद्र बन गए हैं। ये न केवल जटिल समस्याओं के अभिनव समाधानों को डिजाइन करने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बरन् रोजगार के स्वरूप में सुधार, रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्यों के लिए धन सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टार्टअप परिवर्तन सम्बन्धी तकनीक से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और समय के साथ नए उद्योग सृजित करते हैं। स्टार्टअप्स को उपयुक्त आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्रदान करने वाले देशों ने देश के लिए उनके द्वारा बनाए गए सकारात्मक प्रभावों को देखा है। इस प्रकार, उत्तराखण्ड राज्य में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को पोषित करने के लिए, विश्व में कोविड महामारी के बाद आर्थिक वातावरण में भारी बदलाव के महेनजर, घरेलू विकसित स्टार्टअप उद्यमों का समर्थन करने के लिए अनुकरणीय उपायों को डिजाइन करना अपरिहार्य हो गया है। परिणामस्वरूप, राज्य की स्टार्टअप नीति पर किर से विचार करना और उत्तराखण्ड में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अग्रिम विकास हेतु समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, जटिल सामाजिक समस्याओं को हल करने में नवाचारों और उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पूरा करने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों का समर्थन करने के उद्देश्य से, "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2022" प्रख्यापिता की जा रही है।

विश्व में कोविड महामारी के बाद आर्थिक वातावरण में भारी बदलाव के महेनजर, घरेलू विकसित स्टार्टअप उद्यमों का समर्थन करने के लिए अनुकरणीय उपायों को डिजाइन करना अपरिहार्य हो गया है। परिणामस्वरूप, राज्य की स्टार्टअप नीति पर किर से विचार करना और उत्तराखण्ड में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अग्रिम विकास हेतु समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, जटिल सामाजिक समस्याओं को हल करने में नवाचारों और उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पूरा करने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों का समर्थन करने के उद्देश्य से, "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2022" प्रख्यापिता की जा रही है।

उद्देश्य:

इस नीति का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित कर नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे के निर्माण, इन्व्यूबेशन और परामर्शी नेटवर्क की स्थापना, धन तथा बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने, सार्वजनिक खरीद तथा व्यापार के अनुकूल एवं नियामक वातावरण सृजित करने के साथ-साथ राज्य में रोजगार सृजन और धनोत्तरण को बढ़ावा दिलेगा।

दृष्टि:

एक अग्रणी स्टार्टअप गतिव्य का निर्माण कर उत्तराखण्ड को नवोन्मेषी, इच्छुक उद्यमियों, इन्व्यूबेटर्स और पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों (प्लेयर्स) के लिए रणनीतिक स्टार्टअप हब के रूप में प्रतिस्थापित करना।

लक्ष्य:

- आगामी 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों सहित 1000 स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देना।
- नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी, कार्यविधि या प्रक्रियाओं, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, सामाजिक प्रभाव या रिसर्च या काम करने वाले स्टार्टअप उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना, जो जटिल समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रोजगार सृजन और धनोत्तरण के माध्यम से रथानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
- प्रदेश में नवोन्मेषकों, स्टार्टअप्स, इच्छुक छात्र उद्यमियों, महिला उद्यमियों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के लिए अत्याधिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थापना करना।
- प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इन्व्यूबेशन शेन्टर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्व्यूबेशन सेन्टर स्थापित करना।
- राज्य में स्टार्टअप उद्यमों के विकास के लिए पूँजी, प्रमुख बुनियादी ढांचे एवं अन्य प्रमुख संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करना।
- उद्यमशीलता, नवाचारों एवं इसके व्यावसायीकरण तथा प्रौद्योगिकी उद्यगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
- अनुकूल वातावरण का सृजन कर स्टार्टअप उद्यमों का एक अत्यधिक सफल उद्यम के रूप में विकास या रूपान्तरण।

नीति की वैधता:

यह नीति इसकी अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होकर 5 वर्ष या नई नीति लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेगी।

1. परिभाषा:

1.1 विधिक अस्तित्व (इस नीति के अधीन स्टार्टअप्स को मान्यता देने के उद्देश्य से)

विधिक रूप से एक इकाई से अर्थ भारत में निर्गमित निम्नांकित में से किसी एक से है:

- कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या
- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत एक सीमित देयता भागीदारी फर्म या
- साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म।

1.2 સ્ટાર્ટઅપ:

ઉત્તરાખણ્ડ સ્ટાર્ટઅપ નીતિ 2023 કે અધીન એક ઇકાઈ કો "સ્ટાર્ટઅપ" માના જાએગા, યદી વહેં નિર્માલિષ્ટ માનદંડો કો પૂરા કરતી હોય:

ઐસી વિધિક ઇકાઈયાં, જિનકા પંજીકૃત કાર્યાલય ઉત્તરાખણ્ડ મેં હોય:

- (i) યહ એક ઐસી વિધિક અરિતાત્વ વાલી ઇકાઈ હોની ચાહિએ, જેસા કી ખંડ 1 કે ઉપ-ખંડ 1.1 મેં પરિમાણિત કિયા ગયા હૈ; ઔર
- (ii) વિધિક અરિતાત્વ વાલી ઇકાઈ કે ગઠન એવં સંચાલન કી અવધિ ઇસકે નિગમન કી તારીખ સે દસ વર્ષ સે અધિક કી નહીં હોની ચાહિએ; ઔર
- (iii) નિગમન/પંજીકરણ કે બાદ સે કિસી ભી વિત્તીય વર્ષ કે લિએ ઐસી વિધિક ઇકાઈ કા કારોબાર એક સૌ કરોડ રૂપયે સે અધિક કા નહીં હુંબા હૈ; ઔર
- (iv) કિસી મૌજૂદા વ્યવસાય કો વિશેજિત કરકે યા પુનર્નિર્ગાણ કરકે ઇકાઈ કા ગઠન નહીં કિયા જાના ચાહિએ ઔર યહ પારિવારિક વ્યવસાય યા સમૂહ કા હિસ્સા ભી નહીં હોના ચાહિએ ઔર
- (v) ઇકાઈ કો ઉત્પાદો યા પ્રક્રિયાઓં યા સેવાઓં કે નવાચાર, વિકાસ યા સુધાર કી દિશા મેં કામ કરના ચાહિએ, યા યદી યહ રોજગાર સૃજન યા ધનોત્તર્જન કી ઉચ્ચ ક્ષમતા વાળા એક માપનીય વ્યવસાય મૌંડલ હો; યા
- (vi) સમય-સમય પર ભારત સરકાર દ્વારા પરિમાણિત સ્ટાર્ટઅપ કે માનદંડો કે અનુસાર

ઐસી વિધિક ઇકાઈયાં, જિનકા ભારત કે અન્ય રાજ્યો મેં પંજીકૃત કાર્યાલય હૈ

ઇસ નીતિ કે ઉપ ખંડ 1.2 કે અધીન પરિમાણિત માનદંડો કે અતિરિક્ત:

- (i) ઇકાઈ કા ઉત્તરાખણ્ડ રાજ્ય મેં ભી કાર્યાલય હોના ચાહિએ ઔર ઇસ કાર્યાલય કે માધ્યમ સે હી ઉત્તરાખણ્ડ મેં વ્યવસાય કા ગહેરપૂર્ણ સંચાલન હોના ચાહિએ।
- (ii) માન્યતા કી પૂર્ણ અવધિ કે દીરાન ઇકાઈ કો અપને રામગ્ર પૂર્ણકાલિક કાર્યબલ કા ન્યૂનતમ 70 પ્રતિશત ઉત્તરાખણ્ડ કે અધિવાસ વાલે મેં સે નિયોજિત કિયા જાએગા (ઇસ કાર્યબલ મેં સંસ્થાપક, સહ-સંસ્થાપક, સહાયક કર્મચારી, કંપની પેરોલ પર કામ કરને વાલે કુશલ કર્મચારી શામિલ હોણે)।

1.3 ગ્રાસ રૂટ ઇનોવેશન યા ઇનોવેશન/ગ્રામીણ પ્રમાદ કે સાથ સ્ટાર્ટઅપ

ગ્રામીણ પ્રમાદ વાલે ગ્રાસ રૂટ નદોન્ભેષ યા નવોન્ભેષ/સ્ટાર્ટઅપ કો ઇસ પ્રકાર પરિમાણિત કિયા જાએગા:

- (i) ઉત્પાદો યા સેવાઓં કા નિર્માણ યા વિકાસ યા સુધાર જો ગ્રામીણ યા પહાડી ક્ષેત્ર મેં રહને વાલે લોગોં કી સમસ્યાઓં યા ચુનાતીયો યા મુદ્દોં કા સમાધાન કર સકતો હૈને યા
- (ii) ઉત્પાદ યા સેવાઓં કા વિકાસ યા સુધાર જો માપનીય હૈ ઔર જો ધનોત્તર્જન કર સકતા હૈ ઔર ગ્રામીણ યા પર્વતીય ક્ષેત્ર મેં રહને વાલે લોગોં કો આજીવિકા કે અવસર પ્રદાન કરતા હૈ।

ઐસે સ્ટાર્ટઅપ, જો ઉત્તરાખણ્ડ એમ્સેસ્મેન્ટ નીતિ-2015 (સમય-સમય પર યથાસંશોધિત) મેં વર્ગીકૃત

श्रेणी के व खं से आच्छादित क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं और कुछ भवीन समाधानों पर काम कर रहे हैं तथा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों मुद्दों या समस्याओं का समाधान करने या उन्हे आजीविका के अवसर प्रदान करने के तरीकों को यास रुट नवान्वेषी या ग्रामीण प्रभाव वाले नवाधारों की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के रूप में माने जाएँगे।

1.4 असंयत प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप

असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप की अहता निम्नलिखित प्रकार से है-

- (i) भविष्य की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप: स्टार्टअप जो सभाज या देश में विद्यमान समस्या या चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए न्यूरल लैंगेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), ड्रोन, रोबोटिक्स, डिफेंस, एयरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिनटेक मेडिक हेल्थटेक जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं।
- (ii) नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे स्टार्टअप: सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा बायोग्रास ऊर्जा आदि जैसे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों या समाधानों का उपयोग करके ऊर्जा के नवीकरणीय और स्थायी खोत के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करने वाले स्टार्टअप।
- (iii) जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे स्टार्टअप: पर्यावरण के अनुकूल और/या जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों/समाधानों के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऑफसेट करने या क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करते हैं।
- (iv) सर्कुलर इकोनॉमी पर काम कर रहा स्टार्टअप: सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में कार्य करने वाले स्टार्टअप:
 - (क) री-यूज वस्त्रों का संग्रहण सर्कुलर फैशन, सैकेण्ड हैंड प्रोडक्ट्स आदि।
 - (ख) रिसाइकिल: रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स, बोतले रिसाइकिल्ड कच्चेमाल से उत्पादों का निर्माण आदि।
 - (ग) रिड्यूस: धारणीय सामग्री के साथ पैकेजिंग, खाद्य कटलरी आदि।
 - (घ) रिमूव: शहरी खेती, जीवाशम ईंधन का उपयोग, कार्बन कैचरिंग आदि।
- (v) स्थिरता पर काम कर रहा स्टार्टअप: अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक तकनीकों प्रक्रियाओं या समाधानों के साथ हरित और टिकाऊ प्रथाओं पर काम करने वाला एक ऐसा स्टार्टअप, जो दुनिया को बड़े पैमाने पर वर्षों तक अत्यधिक उपयोग से उत्तरने में सक्षम बना रहा है जैसे कि:
 - (क) मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार।
 - (ख) लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण
 - (ग) समुद्र की जैव विविधता का संरक्षण
 - (घ) वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी।
 - (ज) जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी।
 - (च) विशेष क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण और संरक्षण।

(છ) આપદા ગ્રબધન આદિ

1.5 મહિલા ઉદ્યમિયો દ્વારા સ્ટાર્ટઅપ:

એક વિધિક ઇકાઈ કો મહિલા સ્ટાર્ટઅપ કે રૂપ મેં માના જાએગા, યદિ

- (i) ઇકાઈ કી સ્થાપના એક મહિલા ઉદ્યમી દ્વારા કી ગઈ હૈ; ઔર
- (ii) વિધિક ઇકાઈ મેં મહિલા સરથાપકાર્ય કી ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ ઔર/યા ભાગીદારી 51 પ્રતિશત સે કમ નહીં હૈ; ઔર
- (iii) ઇકાઈ મેં મહિલા સક્રિય ભાગીદાર યા નિદેશક હૈ ઔર કથની મેં દિન પ્રતિદિન કે કાર્યો કો સક્રિય રૂપ સે દેખ રહી હૈ।

1.6 અનુસૂચિત જાતિ/ અનુસૂચિત જનજાતિ યા દિવ્યાંગ યા દ્રાસાર્જેભર દ્વારા સ્થાપિત સ્ટાર્ટઅપ

વિધિક ઇકાઈ કો અનુસૂચિત જાતિ/ અનુસૂચિત જનજાતિ યા દિવ્યાંગ યા દ્રાસાર્જેભર દ્વારા સ્થાપિત સ્ટાર્ટઅપ કે રૂપ મેં માના જાએગા, યદિ

- (i) ઇકાઈ કી સ્થાપના અનુસૂચિત જાતિ/ અનુસૂચિત જનજાતિ યા દિવ્યાંગ યા દ્રાસાર્જેભર દ્વારા કી ગઈ હો,
- (ii) અનુસૂચિત જાતિ/ અનુસૂચિત જનજાતિ યા દિવ્યાંગ યા દ્રાસાર્જેભર દ્વારા વિધિક અર્સિટ્યુ વાલી ઇકાઈ મેં ઇવિટી હોલ્ડિંગ ઔર/યા સાઝેદારી 51 પ્રતિશત સે કમ નહીં હોની ચાહિએ, ઔર
- (iii) વિધિક ઇકાઈ મેં અનુસૂચિત જાતિ/ અનુસૂચિત જનજાતિ યા દિવ્યાંગ યા દ્રાસાર્જેભર એક સક્રિય ભાગીદાર યા નિદેશક હો ઔર ઇકાઈ કે દિન-પ્રતિદિન કે કાર્યો કો સક્રિય રૂપ સે દેખ રહા હો

1.7 છાત્ર ઉદ્યમિયો દ્વારા સ્થાપિત સ્ટાર્ટઅપ:

નિયાલિખિત મેં પઢને વાલા કોઈ ભી વ્યક્તિ યા છાત્ર,

- (i) રખૂલ, કોલેજ, પોલિટેકનિક ઔદ્યોગિક પ્રશિક્ષણ રંગથાન (આઈટીઆઈ), યા
- (ii) રાજ્ય યા કેંદ્ર સરકાર દ્વારા સ્થાપિત ઉચ્ચ શિક્ષા (એચીઆઈ). તકનીકી શિક્ષા, વિકિત્ત્વ શિક્ષા યા આયુષ કા કોઈ ભી સંરથાન, યા
- (iii) સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કૌશલ પ્રશિક્ષણ યા વ્યાવસાયિક પ્રશિક્ષણ સંરથાન,
- (iv) કોઈ ભી ગુરૂ વિશ્વવિદ્યાલય ઔર/યા રાજ્ય યા કેંદ્રીય અધિનિયમ કે અધીન સ્થાપિત વિશ્વવિદ્યાલય, યા
- (v) કોઈ અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાન યા વિશ્વવિદ્યાલય જો રાજ્ય યા કેંદ્ર સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત હો

ઐસે અધ્યયનરત છાત્ર, જો સંબંધિત બોર્ડ, સરથાન ઔર/યા વિશ્વવિદ્યાલયો કી ઉચ્ચિત અનુમતિ સે નવાચાર દ્વારા (ઉત્પાદ પ્રક્રિયા પ્રૌદ્યોગિકી યા વ્યવસાય મેં નવાચાર) ઉદ્યમી કે રૂપ મેં ઉદ્યમ કા સંચાલન કર રહે હો

1.8 માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ:

- (i) ખંડ 1 કે ઉપ-ખંડ 1.2 મેં નિર્દિષ્ટ માનદલો કો પૂરા કરને વાલી કોઈ ભી કાનૂની ઇકાઈ ઔર જિસે ઉત્તરાખંડ સ્ટાર્ટઅપ નીતિ કે અધીન સ્થાપિત સ્ટાર્ટઅપ ટાસ્ક ફોર્મ દ્વારા સ્ટાર્ટઅપ કે રૂપ મેં માન્યતા દી ગયી હો કો માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ માના જાએगા।

(ii) उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन गठित स्टार्टअप टारक फोर्स से अनुमोदित ऐसे स्टार्टअप, जिन्हें छात्र उद्यमियों द्वारा स्थापित किया गया हो को मान्यता प्राप्त स्टार्टअप माना जाएगा।

(iii) उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2018 के अधीन स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान को मान्यता प्राप्त स्टार्टअप माना जाएगा।

1.9 टर्नओवर:

टर्नओवर से कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित टर्नओवर अभिप्रैत है।

1.10 स्टार्टअप के चरण:

1.10.1 आइडियेशन चरण:

आइडिया स्टेज स्टार्टअप के जीवन्यक्रम में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें अवधारणा की सफलता/विफलता का मूल्यांकन करने के लिए स्टार्टअप आइडिया का व्यवहार्यता विश्लेषण किया जाता है।

1.10.2 प्रोटोटाइपिंग या न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एम्बीपी) चरण:

प्रोटोटाइपिंग या एम्बीपी चरण एक स्टार्टअप के जीवन्यक्रम में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें उत्पाद या प्रक्रिया या सेवा की अवधारणा को भौतिक रूप में परिवर्तित किया जाता है और जिसे सीमित क्षमता में उत्पादित और वितरित किया जा सकता है तथा सफलता और आवश्यकता पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

1.10.3 स्केल-अप चरण:

स्केल-अप चरण एक स्टार्टअप के जीवन्यक्रम में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें कंपनी मान्य/अंतिम उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं के साथ तैयार होती है तथा बड़े पैमाने पर इसका व्यावसायीकरण करती है।

1.11 नवाचार/नवोन्मेष:

आविष्कार नवाचार का आधार हैं एक आविष्कार तकनीकी समर्था का एक नया सामाजिक संग्रहालय है, जिसे पेटेंट के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है।

नवोन्मेष (इनोवेशन) से कुछ नया करना जै उत्पाद प्रक्रिया या सेवा को बेहतर बनाता है, अभिप्रैत है नवोन्मेष में सराधनों से अधिक या भिन्न मूल्य प्राप्त करने में सूचना, कल्पना और पहल का उपयोग शामिल है। बौद्धिक संपदा अधिकारी (आईपीआर) के अधीन नवाचारों को संरक्षित किया जा सकता है।

1.12 इन्क्यूबेशन सेंटर या इनकूबेटर:

स्टार्टअप कंपनियों को ग्रामीण अवस्था में समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया एक संगठन जो उन्हें व्यापार समर्थन संसाधनों और सुविधाओं, जैसे सह-कार्य स्थान प्रोटोटाइप प्रयोगशाला और उत्पादों या सेवाओं के विकास के लिए उपकरणों के माध्यम से एक मापनीय विजनेस मॉडल के साथ अभिनव उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवा को विकसित करने में मदद करता है इन्क्यूबेशन सेंटर हार्ड और सॉफ्ट इफ्रास्ट्रक्चर, सीड फंडिंग, विजनेस मॉटरिंग और कोचिंग, साझा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। जिसमें अकाउटिंग, कानूनी सेवाएं, मानव संसाधन कॉर्पोरेट कनेक्ट, उद्योग पश्चात्यादाता और निवेशक के साथ जुड़ना एक्सलरेशन कार्यक्रम शामिल होंगे और यह स्टार्टअप्स

के विकास के लिए आवश्यक अन्य सहायता के साथ साथ नेटवर्किंग अवसर प्रदान करेगा, इस नीति के प्रयोजन के लिए एक इनकायूबेशन सेन्टर का अर्थ होगा—

- भारत सरकार के विभागों एजेंसियों या निकायों द्वारा नीतियों या योजनाओं के अधीन वित्त पोषित या पंजीकृत कोई भी सरकार जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनकायूबेटर, नीति आयोग के अधीन अटल इनकायूबेशन सेटर आदि या
- भारत में किसी अन्य राज्य सरकार की नीतियों या योजनाओं के अधीन स्थापित कोई भी विद्यमान इनकायूबेशन सेन्टर जिसकी उत्तराखण्ड में पूर्ण कार्यात्मक सुविधाएँ हैं, या
- इनकायूबेशन सेन्टर की स्थापना के लिए उत्तराखण्ड में पंजीकृत कोई भी नव स्थापित विधिक अस्तित्व याली हकाई

जिसका एकमात्र उद्देश्य समाज के सभी दाँवों के धीर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

1.12.1 इस नीति के प्रयोजन के लिए एक इनकायूबेशन सेन्टर एक अलग विधिक अस्तित्व याली इकाई होगी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है और जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के तहत पंजीकृत हो।

- (i) एक सोसायटी (सोसाइटी) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन); या
- (ii) एक धारा-8 कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन); या
- (iii) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन); या
- (iv) एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के अधीन); या
- (v) एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (ट्रस्ट) (भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन)

1.13 मान्यता प्राप्त इनकायूबेटर:

खंड 1 के उप-खंड 111 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने याली कोई भी ख्वासन्त्र विधिक अस्तित्व याली इकाई और जिसे उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउन्सिल द्वारा इनकायूबेटर के रूप में मान्यता प्रदान की गयी हो को मान्यता प्राप्त इनकायूबेटर माना जाएगा।

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति-2018 के अधीन इनकायूबेटर के रूप में मान्यता प्राप्त सरकारों को मान्यता प्राप्त इनकायूबेटर माना जाएगा।

1.14 लीड इनकायूबेटर:

राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि उत्तराखण्ड में को-वर्किंग स्पेस, कैपिटल इकिव्यपमेट और ऑपरेटिंग सुविधाओं के साथ प्रोटोटाइप लैंब के गामले में आवश्यक भौतिक बुनियादी ढाँचे के साथ विश्व स्तरीय इनकायूबेशन सुविधाएँ विकसित करने की आवश्यकता है, इनकायूबेशन सुविधा राज्य में नवाचार संचालित स्टार्टअप उद्यगों की स्थापना के लिए आवश्यक अन्य प्रासादिक घटकों के साथ-साथ उत्पाद विकास और व्यवसाय नियोजन सहायता, सीड कैपिटल, विषय वस्तु दिशेषज्ञों, कॉरपोरेट्स, प्रौद्योगिकी सहायता प्रदाताओं, उद्योग निकायों त्वरण कार्यक्रमों प्रशिक्षणों तक पहुंच और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान करेगी।

राज्य सरकार प्रदेश के सभी शैक्षणिक सरकारों और व्यावसायिक शिक्षण सरकारों में इनकायूबेशन केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। राज्य में नवाचार और उद्यमिता की स्वस्कृति को बढ़ावा देने

के लिए एक "लीड इनक्यूबेटर" स्थापित करने तथा मायनीय और धारणीय संघर्ष के निर्माण के लिए अभिनव स्टार्टअप व्यवसायों का पोषण करने का भी लक्ष्य होगा। "लीड इनक्यूबेटर" पूरे प्रदेश में स्थापित अन्य मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटरों के लिए हेब के रूप में कार्य करेगा।

1.15 मैन्टर्स:

मैन्टर एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है, जो अपने सचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ-साथ विषय की पूर्ण जानकारी रखता है तथा उसे इच्छुक उद्यमियों को मार्गदर्शन, सलाह और प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक दुनिया का व्यावहारिक अनुभव होता है।

1.16 विषय विशेषज्ञ:

संकेतक मैटर एक प्रमाणित पेशेवर/व्यवसायी होता है जिसके पास डॉमेन विशेषज्ञता, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट कौशल या ज्ञान होता है और अपने क्षेत्र में काम करने का व्यापक व्यावहारिक अनुभव होता है।

1.17 राज्य सरकार:

इस नीति के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार का अर्थ सुल्तानखण्ड सरकार से है।

1.18 राज्य सरकार के अधिकरण (एजेंसियों):

इस नीति के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार की एजेंसियों में विभागों, संरथानों, एजेंसियों, प्राधिकरणों, बोर्डों या किसी भी अन्य निकाय शामिल होंगे जिसमें राज्य विधानसभा के अधिनियम के अधीन स्थापित या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक उपक्रम, सरथा, समिति या न्यास (द्रस्ट) हैं तथा इसमें स्थानीय शहरी निकाय भी सम्मिलित होंगे।

1.19 अकादमी संस्थान:

इस नीति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थान भी इसमें सम्मिलित होंगे, किन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं होगा—

- (i) स्कूल, कॉलेज पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), या
- (ii) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा (एचईआई), तकनीकी शिक्षा, विकित्सा शिक्षा या आयुष का कोई भी संस्थान, या
- (iii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान,
- (iv) किसी राज्य या केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित कोई भी मुक्त विश्वविद्यालय और/या विश्वविद्यालय, या
- (v) कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय जो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

1.20 एक्सलेटर:

एक्सलेटर एक ऐसा संगठन या कार्यक्रम है जो स्टार्टअप्स को अपने ग्राहक आधार बढ़ाने अधिक लाभ कमाने, फंडिंग के लिए तैयार करने और अपने संगठन को पेशेवर बनाने में मदद करने के लिए सलाह, प्रशिक्षण, संसाधन और नेटवर्किंग जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके नए स्टार्टअप के तेजी से विकास को सक्षम बनाता है।

1.21 एजल नेटवर्क:

एक एजल निवेशक (निजी निवेशक, सीड निवेशक या एजल फंडर के रूप में भी जाना जाता है)

एक उच्च निवल मूल्य वाला व्यक्ति है जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप या उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, आमतौर पर कंपनी में इकिटी के रूप में रचायित्व के बदले में।

एजेल नेटवर्क एजेल निवेशकों का एक समूह है जो अपने निवेश को एक साथ रखता है, जिसे प्रारम्भिक चरण के स्टार्टअप में निवेश करने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाता है।

1.22 उद्यम पूजी (वैचर कैपिटल):

वैचर कैपिटल इकिटी फाइंग का एक रूप है जिसमें आम तौर पर उद्यम पूजी फर्मों द्वारा शुरू की गई परियोजना के महत्वपूर्ण मूल्यांकन पर उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्टअप्स में निवेश किया जाता है। यहां पर इकिटी शेयरहोलिंडिंग के बदले में आम तौर पर पूजी का निवेश किया जाता है।

1.23 उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउसिल:

उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउसिल एक शासी निकाय होगी, जिसमें उत्तराखण्ड सरकार, इन्क्यूबेशन सेन्टर उद्योग निकाय, शैक्षणिक संस्थान कॉर्पोरेट, विषय विशेषज्ञ, राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थान, वैचर कैपिटल फर्म या किसी अन्य संगठन के सदस्य शामिल होंगे, जिनके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिविधिकी तत्र में काग करने का व्यापक अनुभव है, जो राज्य सरकार को स्टार्टअप नीति, राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित रणनीतिक पहल से संबंधित मामलों पर सलाह देता है।

1.24 राज्य नोडल एजेंसी:

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2023 में निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने और उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्रित गतिविधियों की देखभाल के लिए उद्योग निदेशालय, एमएसएमई विभाग राज्य नोडल एजेंसी होगा।

1.25 उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रकोष्ठ (सेल):

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन होने वाले दैनिक कार्यों और वित्तीयियों के संचालन एवं देखभाल के लिए एक स्टार्टअप सेल की स्थापना की जाएगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पेशेवर फर्मों के सलाहकारों के साथ एक समर्पित स्टार्टअप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) को राज्य नोडल एजेंसी और स्टार्टअप सेल का समर्थन करने के लिए ऑन-बोर्ड किया जाएगा।

1.26 प्रोत्साहन की मान्यता और संवितरण के लिए टार्क फोर्स या समिति:

राज्य नोडल एजेंसी राज्य सरकार के विभागों उद्यमियों निवेशकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग निकायों विषय वस्तु विशेषज्ञों आदि के सदस्यों को शामिल करते हुए मान्यता देने और प्रोत्साहन धनराशि के वितरण के लिए एक टार्क फोर्स या समिति की स्थापना करेगी।

टार्क फोर्स या समिति निम्नतिष्ठित से संबंधित निर्णय लेगी।

- (क) स्टार्टअप के रूप में मान्यता और वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और मूल्यांकन।
- (ख) मान्यता और वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को मान्यता या प्रोत्साहन प्रदान करना।
- (ग) कोई अन्य निर्णय जैसा कि उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउसिल द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

1.27 सीमित खण्ड:

1.27.1 उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति-2018 के अधीन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, इनक्यूबेटर और नोडल

एजेंसिया के बाल दिनांक 21 फरवरी 2025 तक उक्त नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने की पात्र होंगी।

1.27.2 स्टार्टअप और इनक्यूबेटर जिन्होंने "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2018" के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त किये हैं, वह "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2022" के अधीन समान घटकों पर प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने के लिए अहं नहीं होंगे।

1.27.3 "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2022" के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले स्टार्टअप और इनक्यूबेटर सरकार की किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं में समान घटकों और/या श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन दावा करने के अहं नहीं होंगे।

2. मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन

वित्तीय प्रोत्साहन:

वित्तीय प्रोत्साहन किसी में केवल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को उद्यित मूल्यांकन और उनके स्टार्टअप आइडिया के मूल्यांकन के बाद स्टार्टअप्स की स्थापना के बाद से हुई प्रगति तथा स्टार्टअप्स द्वारा विभिन्न घरणों में प्रस्तुत वित्त पोषण की अवश्यकता के बाद स्वीकृत किये जाएंगे।

2.1 मासिक भत्ता:

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप या छात्र उद्यमियों के स्टार्टअप, जिनकी परियोजना को टारक फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है रु. 15,000 प्रतिमाह प्रति स्टार्टअप का मासिक भत्ता पाने के लिए अहं होंगे।

महिला उद्यमियों के स्वामित्व गें या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दिव्यांग, द्रांसजेंडर या स्टार्टअप के किसी व्यक्ति द्वारा, जो धासरूप पर नवाचारों की दिशा में काम कर रहा है या असंयत प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे ग्रामीण प्रभाव वाले किसी भी नवोन्मेषी स्टार्टअप रु. 20,000 प्रतिमाह/प्रति स्टार्टअप मासिक भत्ते के रूप में देय होगा।

मासिक भत्ता एक बार की सहायता होगी जो स्टार्टअप्स को आइडिया के स्तर पर अधिकतम बारह (12) महीने की अवधि के लिए दी जाएगी।

2.2 सीड फण्ड:

एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो विवार अवस्था या प्रोटोटाइप या एमवीपी (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद) घरण गें है, 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त सीड फण्डिंग सहायता के लिए पात्र होगा।

महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाला स्टार्टअप या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलाग द्रांसजेंडर या ग्रामीण प्रभाव वाले नवाचारों की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के मामले में, 12.5 लाख रुपये तक सीड फण्डिंग सहायता दी जायेगी।

असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप को 2.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सीड फण्डिंग प्रदान की जाएगी।

2.3 बौद्धिक संपदा अधिकार:

भारत सरकार के विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों/योजनाओं के तहत आईपीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहन, लाभ और/या समर्थन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सभी स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अन्य मामलों में, स्टार्टअप आईपीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

पेटेंट

भारतीय पेटेंट के लिए व्यव की गई राशि की शर्त प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु 10 लाख (प्रति पेटेंट) तथा अतर्वाच्चीय पेटेंट हेतु रु. 5.0 लाख (प्रति पेटेंट) प्रत्येक स्टार्टअप को स्वीकृत किया जा सकता। पेटेंट पर प्रतिपूर्ति सहायता के लिए प्रायर आर्ट सर्च गवर्नमेंट फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, मैटेनेस शुल्क या किसी अन्य कानूनी शुल्क के लिए भुगतान किए गए व्यय को गणना में लिया जाएगा।

व्यव की प्रतिपूर्ति दो घरणों में की जाएगी।

(i) पेटेंट आवेदन दाखिल करने के बाद 75 प्रतिशत और

(ii) पेटेंट के अनुदान के समय 25 प्रतिशत।

यह सहायता उस दो कार्यशील पेटेंट दाखिल करने के लिए अनुमत्य होगी जिस क्षेत्र में स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है।

ट्रेडमार्क:

ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने पर रु 10,000 रुपये (प्रति ट्रेडमार्क) तक की प्रतिपूर्ति सह यता दी जाएगी। ट्रेडमार्क अन्वेषण, सरकारी फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क रखरखाव शुल्क या ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने या किसी अन्य कानूनी सहायता के लिए भुगतान किए गए शुल्क पर किये गये व्यय पर ही प्रतिपूर्ति सहायता अनुमत्य होगी।

जिस क्षेत्र में स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है, उसके नाम पर अधिकतम दो ट्रेडमार्क हेतु किये गये व्यय पर प्रतिपूर्ति सहायता अनुमत्य होगी।

औद्योगिक डिजाइन:

औद्योगिक डिजाइन आवेदन जमा करने के लिए 10,000 रुपये (प्रति औद्योगिक डिजाइन) तक की प्रतिपूर्ति। यह प्रतिपूर्ति आवेदन जमा करने के लिए सरकारी फाइलिंग शुल्क अटॉर्नी शुल्क रखरखाव शुल्क या किसी अन्य कानूनी शुल्क के लिए भुगतान की गयी धनराशि पर ही अनुमत्य होगी।

जिस स्टार्टअप के लिए गान्धता प्राप्त की गई है, उसके नाम पर अधिकतम दो डिजाइन हेतु किये गये व्यय पर प्रतिपूर्ति सहायता अनुमत्य होगी।

2.4 एमएसएमई नीति के अधीन प्रोत्साहन:

उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति या सर्व सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं के तहत पात्र स्टार्टअप संबंधित नीतियों और/या योजनाओं के तहत निर्दिष्ट मानदण्ड और उचित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, उत्तराखण्ड सरकार की किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं के अधीन स्टार्टअप समान घटकों और/या श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

2.5 प्री-इन्क्यूबेशन सपोर्ट:

राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अभिज्ञापित असंघत क्षेत्र में काम करने वाले नवोनोवक या महत्वाकांक्षी उद्यमी या महिला/छात्र उद्यमी या ग्रास रुट प्रभाव वाले स्टार्टअप या नवप्रवर्तक/उद्यमी उत्पाद विकास हेतु बेटरिंग तथा हैण्डहैलिंग सपोर्ट पर एक बार निःशुल्क इनक्यूबेशन सहायता के लिए पात्र होंगे।

समय-समय पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अभिज्ञापित प्रतिष्ठित इनक्यूबेशन सेन्टर या एक्सलरेटर के माध्यम से पूर्व-इन्क्यूबेशन कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। प्री-इन्क्यूबेशन सपोर्ट पर चार (4) माह की अवधि के लिए अधिकतम एक बार सहायता प्रदान की जाएगी राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्री-इनक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए रु 10,000 तक प्रति हनक्यूबेटी लागत वहन की जाएगी।

2.6 इन्क्यूबेशन सपोर्ट:

सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप राज्य नोडल एजेंसी के अनुमोदन के अधीन किसी भी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में 12 महीने की अवधि के लिए एकमुश्ति निःशुल्क इन्क्यूबेशन सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

असंघत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप को अतिरिक्त 6 महीने के लिए इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान की जाएगी।

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के तिर मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इन्क्यूबेशन कार्यक्रम में नामांकन की कुल लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जो उप-खंड 3.3 में खंड 3 के अधीन निर्दिष्ट है।

2.7 औद्योगिक क्षेत्र/आईटी पार्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि का प्रावधान:

राज्य सरकार अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों, आईटी पार्कों विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) या किसी अन्य राज्य में रथापित या आधार मूल्य पर औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन करने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को भूमि/स्थान के आवंटन के लिए प्रावधान करेगी।

2.8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर:

राज्य नोडल एजेंसी के अनुमोदन के अधीन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, एक्सपोजिशन, सम्मेलन, संगोष्ठी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एवं सलरेशन कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

સહાયતા કી આવૃત્તિ	ભાગીદારી કી શ્રેણી	સહાયતા
એક	અતરાષ્ટ્રીય	પ્રતિપૂર્તિ સહાયતા હેતુ ગણના મેં લિએ જાને વાલ વચ્ચે/મદ્દ
દો	રાષ્ટ્રીય	<ul style="list-style-type: none"> એકોનોમી કલાસ મેં યાત્રા કરના (એક સરથાપક / સહ-સરથાપક કે લિએ) બજાટ આવાસ (એક સરથાપક / સહ-સરથાપક કે લિએ) સ્ટાલ સ્થાન ભાગીદારી શુલ્ક, યદિ કોઈ હો

2.9 પાયલટ પરિયોજનાઓ:

રીકૃતિ પ્રાપ્ત રાજ્ય સરકાર કે દસ્તાવેજોને સાથ ઉત્પાદોન્યા સેવાઓની અવધારણા, પરીક્ષણ ઔર બાજાર સત્યાપન કે પ્રમાણ કે લિએ એક પાયલટ પરિયોજના કે લિએ એક વાર મેં રૂ. 3 લાખ તક કી સહાયતા અનુમન્ય હોયો અસયત પ્રીયોગિકી પર કામ કરને વાલે સ્ટાર્ટઅપ્સ કો રૂ. 2.5 લાખ તક કી અતિરિક્ત વિત્તીય સહાયતા પ્રદાન કી જાએની

સ્ટાર્ટઅપ કો સંબંધિત સરકારી એજેસી સે પાયલટ પ્રોજેક્ટ કે લિએ આશય પત્ર પ્રાપ્ત હોના ચાહેરે।

2.10 એકસલરેશન પ્રોગ્રામ:

રાજ્ય સરકાર પ્રત્યેક વર્ષ કાગ સે કમ દો એકસલરેશન કાર્યક્રમોની આયોજન ઉદ્યમ પૂર્જી ફર્મોની યા પ્રારિદ્ધ એકસલરેટર યા કોર્પોરેટ ઘણને યા એકસલરેશન પ્રોગ્રામ કો ડિજાઇન કરને ઔર આયોજિત કરને મેં વિશેષજ્ઞતા રખને વાલે કિસી અન્ય માન્યતા પ્રાપ્ત પેશેવર સંગઠન કે સાથ સાડેદારી મેં કરેગી।

2.11 બાહ્ય ફણિંગ તક પહુંચ:

વિત્ત પોષણ કે અવસરોની તક પહુંચ કો સુવિધાજનક બનાને કે લિએ રાજ્ય સરકાર પાત્ર સ્ટાર્ટઅપ્સ કો બાહ્ય નિવેશકો દ્વારા વિત્તીય સરથાનોની, વિત્ત પોષણ નિકાયોની ઉદ્યમ પૂર્જીપત્રિયોની નિવેશ નેટવર્ક આદિ સે સુવિધાજનક શર્તોની (ઉદાહરણ કે લિએ પ્રાથમિકતા કે આધાર પર ક્રાણ સંપાર્શીક મુલ્લ ક્રાણ આરાન ક્રાણ આદિ) પર ધન જુટાને કા અદસર પ્રદાન કરને કે લિએ એક તત્ત્વ ઔર/યા એક સંચ સ્થાપિત કરેગી।

गैर-वित्तीय प्रोत्साहन:

2.12 ईज ऑफ बुईग विजनेस:

व्यक्तिगत शुरू करने में विभिन्न विभागीय अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करना सम्मिलित है इस प्रकार, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार को नियमित अनुपालन, दण्डालक कार्रवाइयों को कम करने और अगले धरण के आर्थिक विकास के इन प्रणालिकों को सहायता / जागरूकता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए।

राज्य सरकार नियमितों को कम करने और यह प्रमाणन को प्रोत्साहित करके ईज ऑफ बुईग विजनेस को बढ़ाएगी। सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप नियमित अधिनियमों के तहत मान्यता की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए यह-प्रमाणन के आधार पर नियमण से छूट के पात्र होंगे।

- (i) कार्रवाना अधिनियम, 1948
- (ii) दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम,
- (iii) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1981
- (iv) रेका अम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- (v) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1938
- (vi) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- (vii) रोजगार विनियम अधिनियम, 1958
- (vii.i) उपदान (Gratuity) संदाय अधिनियम, 1972
- (ix) वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- (x) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (xi) भवन और अन्य निर्माण अभिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1998
- (xii) अंतर्राजीय प्रदानी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979
- (xiii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीण उपबन्ध अधिनियम, 1952
- (xiv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- (xv) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा इस सम्बंध में अधिसूचित कोई अन्य अधिनियम, नियम, विनियम

उपरोक्त अधिनियमों के अधीन छूट उद्योग समर्थन और आतंरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया या राज्य उथवा केंद्र सरकार के सम्बित विभागों द्वारा या सम्बित अधिनियमों, नियमों या विनियमों के अधीन निर्दिष्ट उपचित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन होगी।

2.13 लोक अधिप्राप्ति:

उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं उसके अन्तर्गत किये गये संशोधनों के अनुसार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समर्त स्टार्टअप सार्वजनिक उपाय में छूट के पात्र होंगे। राज्य सरकार के अभिकरण (एजेसिया) सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति और अधिप्राप्ति नियमों (समय-समय पर यथासंभवित) के अधीन निर्दिष्ट छूट का विस्तार करेंगे।

राज्य सरकार के सभी संस्थाओं या विभागों या उपक्रमों को उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति के अधीन पंजीकृत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स से 10 लाख रुपये तक (जीएसटी को छोड़कर) की सीधे क्रय करने की अनुमति होगी।

2.14 साझा सुविधाओं तक पहुंच

राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी प्रयोगशालाओं उत्कृष्टता केन्द्रों, पुस्तकालयों या किसी अन्य साझा सुविधाओं में संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने की व्यवस्था करेगी, जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा नवीन विचारों/अवधारणाओं और/या उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

2.15 निःस्वार्थ सेवाएँ

राज्य सरकार पेशेवर संगठनों, कॉर्पोरेट्स या अन्य संगठनों और सेवा प्रदाताओं के साथ एल एंड डी मॉड्यूल, नियेशक पिच डेक आदि के लिए उपकरण और टैम्पलेट जैसे प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करने के लिए साझेदारी रथापित करेगी और उत्पादों या सेवाओं के विकास में स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए एकाउटेंसी, विधिक सहायता, मानव संसाधन विवाद सेवाओं आदि जैसे हैंडहोल्डिंग स्पोर्ट प्रदान करेगी।

2.16 कुशल मानव संसाधन

राज्य सरकार कुशल और अकुशल मानव संसाधन की भर्ती के लिए स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित करेगी जिसके माध्यम से मानव संराधनों की भर्ती पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, उत्तराखण्ड कौशल विकास बिशन, शैक्षणिक संस्थानों में की जा सकती है।

2.17 मुद्रों या शिकायतों का समाधान

राज्य सरकार एक एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी, जो स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स निवेशकों, इच्छुक उद्यमियों के समस्याओं या शिकायतों की पहचान करने की अनुमति देगी और समयबद्ध तरीके से समस्याओं या शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र रथापित करेगी।

राज्य सरकार की राष्ट्रीय एजेंसियों स्टार्टअप्स इनक्यूबेटर्स, नियेशकों इच्छुक उद्यमियों और अन्य परिस्थितिकी तंत्र के प्लेटफॉर्म की समरयाओं या शिकायतों की पहचान और समाधान के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी विकसित करेगा, जो सबधित एजेंसियों से राष्ट्रियता हो।

2.18 नीतियों और योजनाओं पर सार्वजनिक परामर्श

राज्य सरकार लोक अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा बनाई गई नीतियों योजनाओं के नियमों विनियमों, सरकारी आदेशों आदि पर स्टार्टअप्स से परामर्श करने के लिए एक तंत्र रथापित करेगी।

ताकि नीति को अन्तिम रूप देते समय उनके सुझावों पर विचार किया जा सके,

जीपीएस रिस्टम, सर्कुलर इकोनॉमी सर्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, बिग डेटा फिनेंटेक, परिवहन, शहरी गतिशीलता, ई बाहन, बायोटेक, हेल्थकेयर ई-फार्मसी, नागरिक उद्ययन, अपशिष्ट पुनर्वर्क्षण अतरिक्ष प्रौद्योगिकी ड्रान, रोबोटिक्स पर्टीटन यात्रा तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन चिकित्सा उपकरण आदि जैसे असाध्य क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स से राज्य सरकार अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा स्टार्टअप से सबधित क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली नीतियों योजनाओं के नियमों विनियमों सरकारी आदेशों आदि को हैंयार करते समय परामर्श लिया जाएगा।

3. इन्व्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहन:

3.1 लीड इन्व्यूबेटर्स:

राज्य सरकार उत्तराखण्ड में निर्माण, परिवहन ऊर्जा रसायन शिक्षा, कृषि जल एवं स्वच्छता आदि क्षेत्रों में विश्व स्तरीय इन्व्यूबेशन केंद्रों अथवा सत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करेगी। इस इन्व्यूबेशन केंद्रों और/या सीआई का उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स या स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना होगा, जो जमीनी स्तर की घुनौतियों का समाधान कर रहे हैं जिनका अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग और/या प्रभाव है।

3.2 इन्व्यूबेशन केंद्रों के लिए पूँजीगत अनुदान:

राज्य सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पर कॉर्पोरेट्स, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यावसायिक रांगठनों एवं सलरेटर्स आदि के साथ साझेदारी में अत्यधिक इन्व्यूबेशन केंद्रों की स्थापना का प्रयास करेगी। उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप परिषद द्वारा स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त इन्व्यूबेशन केन्द्र भूमि एवं भवन की लागत को छोड़कर एकमुश्त पूँजीगत अनुदान के पात्र होंगे।

विवरण	सहायता की राशि	सहायता की सीमा
नए इन्व्यूबेशन केंद्रों की स्थापना	₹. 1 करोड़ तक	अधिकतम 50 प्रतिशत धनसंशि द्धय करने के प्रस्ताव पर
मौजूदा इन्व्यूबेशन केंद्रों का विरतार	₹ 50 लाख तक	अधिकतम 50 प्रतिशत धनसंशि द्धय करने के प्रस्ताव पर

पूँजीगत अनुदान का वितरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट योजना तथा उत्तराखण्ड स्टार्ट-अप परिषद द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट योजना के अधीन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जायेगा। आवेदक आवेदन करते समय प्रस्तुत वार्षिक बजट योजना के साथ इन्व्यूबेशन केंद्र चलाने के लिए स्पष्ट रूप से व्यवसाय मॉडल को परिभाषित करेगा और वह पांच वर्ष की अवधि में स्वतंत्रतायी हो जाएगा।

3.3 इन्व्यूबेशन केंद्रों के लिए प्रचालन अनुदान:

उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त इन्व्यूबेटर खण्ड 2 के उपर्युक्त 2.6 में निर्दिष्ट स्टार्टअप को इन्व्यूबेशन सहायता प्रदान करने की लागत को कवर करने के लिए प्रति स्टार्टअप 100 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति सहायता के पात्र होंगे। मान्यता प्राप्त इन्व्यूबेशन केंद्रों को ₹ 5 लाख तक की अतिरिक्त एकमुश्त सहायता केस-दू-केस बेसिस पर उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउन्सिल के अनुमोदन के अधीन प्रदान की जाएगी।

मान्यता प्राप्त इन्व्यूबेशन सेन्टर परिचालन अनुदान के लिए संधालन में आने के बाद अहं होंगे और परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को इन्व्यूबेट करना प्रारम्भ कर देंगे। प्रचालन अनुदान सहायता, राज्य नोडल एजेंसी को संधालन की लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुगम्य होगी। इन्व्यूबेटर कम से कम 12 माह की अवधि के लिए और अधिकतम 18 माह की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को भौतिक रूप से इन्व्यूबेट करेगा।

इन्व्यूबेशन केंद्र राज्य नोडल एजेंसी को निर्दिष्ट प्रारूप में इन्व्यूबेटी स्टार्टअप द्वारा की गई प्रगति की त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

3.4 शैक्षणिक संस्थानों में इन्व्यूबेशन सेंटर:

विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा, विकित्सा शिक्षा पॉलिटेक्निक कॉलेज स्कूल आदि प्रोटोटाइपिंग प्रयोगशालाओं के साथ एक बुनियादी इन्क्यूबेशन सुविधा और संसाधन जैसे कि भौगोलिक संसाधन, हार्ड एवं सॉफ्ट बुनियादी दाचागत संसाधन प्रक्रिया और शिक्षण शास्त्र से जुड़े संसाधन और उनके परिसर के भीतर क्षेत्रीय प्रणालिया स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

प्रत्येक इन्क्यूबेशन केंद्र, छात्र नवाचार और उद्यमिता परिषद की गी रथापना करना परिषद की देखभाल के लिए मानव संसाधनों को नियुक्त करेगा। लघु और दीर्घकालिक कार्यसूची विकसित करने के लिए ऐसी सुविधा के समन्वय हेतु एक वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करेगा।

नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन राज्य या कैंपस सरकार द्वारा रथापित शैक्षणिक संस्थानों को प्रस्तावित बजट का 100 प्रतिशत तक और निजी क्षेत्र में स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रस्तावित बजट का 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देय होगी।

वित्तीय सहायता	दिश्वविद्यालय	संस्थान और कॉलेज	पॉलिटेक्निक, आईटीआई, स्कूल आदि।
नए इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए पूँजीगत अनुदान	रु. 1 करोड़ तक	रु. 30 लाख तक	रु. 20 लाख तक
मौजूदा इनक्यूबेशन केंद्रों के विस्तार के लिए पूँजीगत अनुदान	रु. 50 लाख तक	रु. 20 लाख तक	रु. 10 लाख तक
परिचालन अनुदान	जैसा कि खंड 3 के उप-खंड 3.3 में निर्दिष्ट है	जैसा कि खंड 3 के उप-खंड 3.3 में निर्दिष्ट है	जैसा कि खंड 3 के उप-खंड 3.3 में निर्दिष्ट है

4. शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देना:

4.1 उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई-सेल):

राज्य सरकार द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के अधीन रथापित सभी शैक्षणिक संस्थान उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई-सेल) रथापित करेंगे और सभी निजी तौर पर रथापित शैक्षणिक संस्थानों को उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई-सेल) रथापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और छात्रों को अपने परिसर में उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। शैक्षणिक संस्थान ई-सेल के दैनिक संचालन की देखभाल के लिए एक स्टार्टअप नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

वर्षभर उद्यमिता पर केंद्रित गतिविधियों के आयोजन के लिए सभी ई-सेल स्टार्टअप उत्तराखण्ड से सबद्ध होंगे। सभी ई-सेल स्टार्टअप उत्तराखण्ड के सहयोग से स्टार्टअप बूट कैंप बिजनेस स्लान प्रतियोगिता स्टार्टअप पिच फेस्ट आइडिया चैलेज, ग्रैंड चैलेज हैकथॉन आदि का आयोजन उन छात्रों के लिए करेंगे, जो उद्यमिता अपनाने के इच्छुक हैं।

स्टार्टअप उत्तराखण्ड से सबद्ध ई-सेल कार्यक्रमों के संचालन के खर्च को पूरा करने के लिए प्रति कार्यक्रम रु. 1,00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

4.2 छात्र स्टार्टअप उद्यमी-

राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित नवीन रहार्टअप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी पूर्व इन्क्यूबेशन समर्थन के लिए पात्र होंगे जैसा कि खण्ड 2 के उप-खण्ड 2.5 में निर्दिष्ट है और मासिक भत्ता खण्ड 2 के उप-खण्ड 2.1 में निर्दिष्ट है येजुएशन और पौरस्ट येजुएशन के छात्र उद्यमियों को उनकी स्टार्ट अप परियोजना को उनकी डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त परियोजना या अतिम वर्ष की परियोजना के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

स्टार्टअप उत्तराखण्ड समय समय पर विचार, प्रोटोटाइप, एमवीपी, फील्ड-प्रीक्षण, बाजार अनुसंधान और फाइलिंग आईपीआर के सत्यापन के लिए प्रारम्भिक शोध करने के लिए प्रारम्भिक प्रारम्भ के लिए छात्र उद्यमियों की सुविधा के लिए तंत्र स्थापित करेगा।

4.3 उद्यमिता पर पाठ्यक्रम-

सभी शैक्षणिक संस्थान एक छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के साथ-साथ कार्य योजना और अच्छी तरह से परिमित अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करेंगे जो उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति- 2023 और राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति 2019 के अनुरूप होना चाहिए।

उद्यमिता संवर्धन और विकास शैक्षणिक संस्थान की रणनीति के प्रमुख आयामों गे से एक होना चाहिए राज्य नोडल एजेंसी उद्यमिता विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम को डिजाइन और विकसित करेगी।

सभी शैक्षणिक संस्थान छात्रों को ज्ञानरूप करने और उन्हें अपने कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्त्वाहित करने के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में "उद्यमिता विकास" पर पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए आगे पाठ्यक्रम को अद्यतन करेंगे।

सभी शैक्षणिक संस्थान समर कैप कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उत्तराखण्ड स्टार्टअप सेल के सहयोग से चिन्हित छात्रों के लिए "नवाचार और उद्यमिता विकास" पर केंद्रित कम से कम एक समर्पित पाठ्यक्रम भी आयोजित करेंगे।

4.4 व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) को पाठ्यक्रम में शामिल करना:

नवाचार और उद्यमिता पर केंद्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रत्त पर मान्यता प्राप्त व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज या राज्य सरकार द्वारा डिजाइन एवं अनुमोदित किसी अन्य व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्टअप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इन एमओओसी को इध्युक छात्र उद्यमियों द्वारा वैकल्पिक विषयों के रूप में लिया जा सकता है और उनकी रुचि के आधार पर उन्हें समुन्देशित किया जा सकता है।

4.5 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:

नवाचार और उद्यमिता युवाओं को महत्वपूर्ण खोजों की ओर प्रेरित कर सकते हैं, युवाओं को उद्यमिता की ओर ले जाने में शिक्षकों, शिक्षकों और प्रशार्मदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उद्यमिता के क्षेत्र में उद्योग जगत के दिग्गजों, कॉरपोरेट और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विषय विशेषज्ञों द्वारा विकास के लिए शिक्षकों शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा।

शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की एजेंसियों में विशेषज्ञ के लिए स्टार्टप्स पर केंद्रित प्रशिक्षण और क्षमता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹ 1.00 लाख तक की प्रति संस्थान/ प्रति कार्यक्रम/प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी।

4.6 સ્ટાર્ટઅપ કે સલાહકાર કે રૂપ મેં સંકાય:

સમી શિક્ષણિક સરથાનોં મેં શિક્ષકોનો એક નિર્ધારિત સમય કે લિએ ઇનવ્યૂબેટર સેન્ટર યા ઉદ્યમિતા વિકાસ પ્રકાષ્ટો (ઇંડીરી) મેં ઇચ્છુક છાત્ર ઉદ્યમિયોને સાથ સંકાક કે રૂપ મેં કામ કરને કે લિએ સમય નિકાલને કે લિએ પ્રોત્સાહિત કિયા જાએગા, જિસકે બાદ વેં અપને સામાન્ય કામ મેં વાપસ આ સકોણો!

4.7 ઉદ્યોગ ઔર શિક્ષા જગત કે થીચ સાઝેદારી:

ઉદ્યોગ અકાદમિક સહયોગ એક સ્થાયી પારિસ્થિતિકી તત્ત્વ કે લિએ મહત્વપૂર્ણ હૈ જહાં ઉદ્યોગ ઔર શિક્ષા દૌનોં ફળતો ફૂલતો હૈને, અનુસંધાન પરિયોજનાઓનો આગે બढાને, નવ્યાગ્રાસોનો ઉત્તોરિત કરને ઔર પ્રીદ્યોગિકી વિકાસ ઔર કુશલ કાર્યબલ કે નિર્માણ કે લિએ ઉદ્યોગ ઔર કોર્પોરેટ્સ કે સાથ સાઝેદારી બહુત મહત્વપૂર્ણ હૈને।

રાજ્ય સરકાર ઉદ્યોગ ઔર શિક્ષણિક સરથાનોને થીચ સાઝેદારી કો સક્ષમ કરને કે લિએ એક તત્ત્વ સ્થાપિત કરેણી।

4.8 શિક્ષણિક સરથાનોનો નવાચાર કા વ્યાવસ્થાયીકરણ:

નવાચાર ઔર ઉદ્યમશીલતા કી સંરકૃતિ કો વિકસિત કરના ઔર સ્ટાર્ટ-અપ્સ કો સમય પર સહાયતા પ્રદાન કરના વાર્તાવ મેં એક પ્રાગતિશીલ અર્થવ્યવરસ્થા કે લિએ સૌંક-સૌંલિડ ફાઉન્ડેશન બનાતા હૈ અગાલી પીડી કે સ્ટાર્ટઅપ બનાના સમય કી માંગ હૈ। વિશ્વવિદ્યાલયોને સ્કૂલોનો કોલેજો, પોલિટેકનિક ઔદ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન (આઈટીઆઈ), તકનીકી શિક્ષા સરથાનોને, ચિકિત્સા શિક્ષા આદિ જેસે શિક્ષણિક સરથાનોને દ્વારા કિએ જા રહે અનુસંધાન અગ્રિમ અગાલી પીડી કે સ્ટાર્ટઅપ કે નિર્માણ મેં બહુત મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભા સકતે હૈને

ઉત્તરાખણ્ડ મેં સમી શિક્ષણિક સરથાનોનો અનુસંધાન ઔર વિકાસ પરિયોજનાઓનો પેટેટ વિચારોનો યા કિસી ભી અન્ય પરિયોજનાઓનો તક પહુંચ પ્રદાન કરને કે લિએ પ્રોત્સાહિત કિયા જાએગા, જો અકાદમિક અનુસંધાન ખોજોનો સફળ વ્યાવસાયિક ઉપક્રમો મેં બદલને કે ઉદ્દેશ્ય સે ઇચ્છુક છાત્ર ઉદ્યમિયોનો, સ્ટાર્ટઅપ્સ ઔર ઉદ્યોગોનો સદરસ્યોનો કે લિએ વ્યાવસાયિક મૂલ્ય રખતે હૈને।

ઇસકા ઉદ્દેશ્ય અનુસંધાન ઔર વ્યવસાય દૌનોં કો લાભ પહુંચાના હૈ ઔર નેડ તકનીક કે ઉપયોગ મેં આને પર ના મૂલ્ય કા નિર્માણ કરના હૈ।

5. સામાન્ય પ્રાવધાન:

5.1 સંસ્થાગત સમર્થન:

(i) સ્ટાર્ટ-અપ પોર્ટલ ઔર મોબાઇલ ઐપ:

સ્ટાર્ટઅપ પોર્ટલ કે માધ્યમ સે સ્ટાર્ટઅપ નીતિ, સરકારી અધિસૂચના, માન્યતા કે લિએ આવેદન ઔર પ્રોત્સાહન આદિ સે સર્વાધિત સમી જાનકારી તક પહુંચ પ્રદાન કરને કી આવશ્યકતા કો દૃષ્ટિગત રખતે હુએ રાજ્ય સરકાર ઉત્તરાખણ્ડ સ્ટાર્ટઅપ પોર્ટલ ઔર ઐપ કો અપણેઢ કરેણી

(ii) સમર્પિત હેલ્પલાઇન:

સ્ટાર્ટઅપ સે સર્વાધિત સમી પ્રશ્નાનો કે લિએ હૈન્ડહોલ્ડિંગ સહાયતા પ્રદાન કરને કે લિએ એક સમર્પિત હેલ્પલાઇન અગ્રેજી ઔર હિંદી મેં વિકસિત કી જાએણી, હેલ્પલાઇન

व्यवसाय पर्याप्ति, धन/ऋण जुटाने, नीति स्पष्टीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में सभी प्रश्नों को संबोधित करने में सहायता करेगी।

5.2 फैब लैब या मेकर्स लैब या प्रोटोटाप्ल लैब

इनोवेटर्स स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स के लिए फैब लैब मेकर लैब्स या उत्पाद विकास, परीक्षण और सत्यापन, इटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए धन का प्रावधान किया जाएगा। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में राज्य सरकार कम से कम दो प्रयोगशालाओं की स्थापना सुनिश्चित करेगी।

5.3 प्रैंगणित कार्यक्रम

उद्यमिता के माध्यम से जटिल समस्याओं के समाधान हेतु युवाओं को आकर्षित एवं अभियोगित करने के लिए राज्य नोडल विभाग और अन्य विभाग, एजेंसियां, निकाय, निगम, शहरी स्थानीय निकाय, प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं

- (क) उत्तराखण्ड के दो अलग-अलग क्षेत्रों में कम से कम दो राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे उत्तराखण्ड इनोवेशन थीक, स्टार्टअप टेकफेर्ट, स्टार्टअप फॉरेंजिंग इवेंट, उत्तराखण्ड स्टार्टअप कॉन्फ्लेक्चर आदि आयोजित करने।
- (ख) जिलेवार स्टार्टअप बूट कैंप और कम से कम एक आहंकिया चैलेज, ग्रैंड चैलेज, रसरल इनोवेशन चैलेज हैकथॉन आदि का आयोजन करें। राज्य भर के इनोवेटर्स से नए विचारों और परियोजनाओं की तलाश करने।
- (ग) उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रदर्शनी, स्टार्टअप उत्पाद शोकेस, डेमो डे/डिमांड डे, बी2जी और बी2बी कार्यक्रम आदि जैसे स्टार्टअप्स को बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए कम से कम एक कार्यक्रम आयोजित करने।

वार्षिक रूप से चुनौतियों/प्रतियोगिताओं के दौरान एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए शीर्ष शीर्ष अभिनव स्टार्टअप विचारों को रु. 2.0 लाख का सीड फॉड प्रदान किया जाएगा, जो उनकी सफलता की कहानियों के प्रकाशन के साथ-साथ अनुदान सहायता और इन्क्यूबेशन सहायता के रूप में होगा।

5.4 संवेदीकरण कार्यक्रम:

जागरूकता पैदा करने और राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता की सहकृति बनाने के लिए राज्य नोडल एजेंसी राज्य के सभी जिलों को कवर करने वाले इच्छुक उद्यमियों, इन्क्यूबेटर्स, निवेशकों सरकारों, उद्योग के सदस्यों, पेशेवरों और अन्य पारिस्थितिकी तत्र के समर्थकों के भागदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता के लिए स्टार्टअप संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

5.5 फॉन्ड्स ऑफ फॉन्ड्स या वैंचर फॉड:

स्टार्टअप में निवेश के लिए इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें रकेल अप हेतु इक्विटी फॉड के रूप में अपने उद्यम को विकसित करने तथा विकास के लिए सक्षम बनाने हेतु वैंचर फॉड में निवेश करने हेतु फॉन्ड्स ऑफ फॉन्ड्स के रूप में रु. 200 करोड़ की निधि आवंटित की जाएगी। निधियों के संचालन और प्रबंधन के लिए खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक पेशेवर निधि प्रबंधक का चयन किया जाएगा। राज्य में लीड इन्क्यूबेटर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निधियों के एक हिस्से का उपयोग किया जा सकता है।

રાજ્ય સરકાર કી એઝેસિયા ઇવિક્ટી કે બદલે નવીન આંડ્રૂ/યા પ્રોફોગિકી ઉન્નુખ સ્ટાર્ટઅપ મેં નિવેશ કરને કે લિએ અપને બજટ સે ક્ષત્ર વિશિષ્ટ ઉદ્યમ નિધિ મી સ્થાપિત કર સકતી હૈને.

5.6 એઝેલ નેટવર્ક કી સ્થાપના:

ઉત્તરાખણ્ડ સરકાર ઉદ્યોગપતિયાં, પેશેકરોં વ્યક્તિગત નિવેશકો, ઉચ્ચ નિવલ મૂલ્ય વાળે વ્યક્તિયો અનિવારી ભારતીય સામાજિક પ્રમાદ નિવેશક સમૂહોનો કો એજેલ્સ નેટવર્ક સ્થાપિત (ઉત્તરાખણ્ડ એજેલ્સ) કરને કે લિએ સંવેદનશીલ બનાએગી તાકિ ઉત્તરાખણ્ડ સે સંચાલિત સ્ટાર્ટઅપ્સ કે લિએ પ્રારમ્પિક ઘરણ કે વિત્ત પોષણ કે વૈકલ્પિક શ્રોત કો સહામ બનાયા જા સકે

5.7 રાજ્ય સરકાર કી એઝેસિયો દ્વારા કી જાને વાળી ગતિધિયિયાં:

રાજ્ય સરકાર કી સામી એઝેસિયા નિર્માલિખિત ગતિધિયિયાં કે નિર્વહન કે લિએ ઉત્તરદાયી હોણી:

- (i) એસી સ્ટાર્ટઅપ નીતિયો સુવિન્યસ્ત કરેંણે જો સ્પષ્ટ રૂપ સે સ્થાયી કાર્યક્રમો, હૈક્યુરોન ભવ્ય ચુનીતિયો, ઇન્સ્યુબેશન રૂપોર્ટ, પરામર્શ સમર્થન, વિત્ત પોષણ સમર્થન સાર્વજનિક ખરીદ, ઉદ્યમ વિત્ત પોષણ ઓપન ડેટા એપિસ ઔર અન્ય ટિકાઊ કાર્યક્રમો કે રૂપ સે સ્ટાર્ટઅપ કો સરથાગત સમર્થન પ્રદાન કરને કે લિએ વાર્ષિક યોજના કો પરિબાસીત કરના।
- (ii) સ્થાપિત સ્ટાર્ટઅપ હૈલ્પસેસ્ક ઔર ઇસકે સંચાલન ઔર પ્રવધન કી દેખભાલ કે લિએ એક નોડલ અધિકારી નિયુક્ત કરેણે, તાકિ ઇચ્છુક સ્ટાર્ટઅપ ઉદ્યમીયો કો આવશ્યક માર્ગદર્શન ઔર સહાયતા પ્રદાન કરના।
- (iii) માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ કો તકનીકી સહાયતા, સલાહ ઔર અન્ય સહાયતા પ્રદાન કરને કે લિએ કોર્પોરેટસ, ઉદ્યોગ સંઘો યા પેશેકર સંગઠનો કે સાથ સાડોદારી સ્થાપિત કરના
- (iv) સ્ટાર્ટઅપ્સ કી બારીકીયો પર માર્ગદર્શન, પરામર્શ ઔર પ્રશિક્ષણ કે લિએ સરકારી અધિકારીયો કે લિએ પ્રશિક્ષણ ઔર ક્ષમતા નિર્માણ કાર્યક્રમ આયોજિત કરના।
- (v) ઇસસે સંવધિત સમયાઓ યા શિકાયતો કી પહ્યાન કરને ઔર સગયબદ્ધ તરીકે સે ઉનકે સમાધાન કે લિએ એક ઑનલાઇન તંત્ર સ્થાપિત કરના।
- (vi) માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપસ કો ભવ્ય ચુનીતિયો, વિધાર ચુનીતી ડેમો ડે/હિમાંડ ડે, ઇનોવેશન ડે આદી કે માધ્યમ સે પાયલટ પ્રોજેક્ટ સે ગુજરને કે અધિકાર કે રૂપ મેં અયસર પ્રદાન કરેણે, તાકિ વે અપને ઉત્પાદ ઔર સેવાઓ કો પરીક્ષણ ઔર સત્યાપન કરના।
- (vii) ઉત્તરાખણ્ડ ક્રય વરીયતા નીતિ અધિપ્રાપ્તિ કે નિયમો (સમય-સમય પર યથાસથોધિત) કે અનુસાર સામી સાર્વજનિક અધિપ્રાપ્તિ મેં સામી માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટઅપ કો છૂટ પ્રદાન કરના।
- (viii) સંવધિત રાજ્ય નોડલ એઝેસિયો કી મીજૂદા યા કિન્હી નર્દ યોજનાઓ નીતિયો નિયમો, વિનિયમો, સરકારી આદેશા આદી મેં કિએ જાને વાળે પરિવર્તનો પર ઉનકે સુઝાવો કો આસ્ત્રિત કરને કે લિએ સ્ટાર્ટઅપ કે સાથ પરામર્શ કરના, તાકિ ઉનકે સામને આને વાળી ચુનીતી કો સમાધાન કિયા જા સકે।
- (ix) સ્ટાર્ટઅપ્સ કે લિએ પરેશાની રહિત ઔર સમયબદ્ધ વૈધાનિક મજૂરી કો સક્ષમ બનાના।

(x) खंड 5 के उप-खंड 5.2 में निर्दिष्टानुसार वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करना।
 (xi) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली अन्य गतिविधिया।

5.8 हैकथॉन या आइडिया बैलेंज़:

जटिल समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकार की एजेंसियां अपने सबधित क्षेत्रों से एक समस्या क्षेत्र या चुनौतियों की पहचान करेंगी और उन समस्याओं को हल करने के लिए अधिनव समाधान विकसित करने के लिए सभी स्टार्टअप्स का आमंत्रित करेंगी।

स्टार्टअप्स द्वारा इस तरह से डिजाइन व विकसित किए गए तथा कठोर दबाव प्रक्रिया के माध्यम से धुने गए समाधानों को प्रारम्भिक अनुदान दिया जाएगा और सबधित विभाग, एजेंसियों, या निकायों निगमों, प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों या अन्य सरकारी में एक उपयुक्त पैमाने पर एक पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वयन के लिए लिया जा सकता है।

हैकथॉन/आइडिया बैलेंज़/इनोवेशन बैलेंज के आयोजन के लिए और विजेता आइडियाज को पायलट प्रोजेक्ट के लिए मौका देने हेतु निधि का प्रावधान संबधित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

5.9 महिलाओं के बीच सद्व्यवहार को प्रोत्साहित करना:

राज्य सरकार की सभी एजेंसियां उद्यगिता में महिलाओं को बढ़ाया देने के लिए अपने संबधित क्षेत्रों में कार्यक्रमों और पहलों को डिजाइन और कार्यान्वयित करेंगी और महिला स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह देने के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगी। महिलाओं पर केंद्रित कम से कम दो कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण के लिए एक वर्ष में आयोजित किए जाएंगे, इसके लिए संबधित विभाग, अधिकरणों (एजेंसियां), निकाय अपने बजट से धनराशि का प्रावधान करेंगे।

राज्य सरकार सभी समर्थित इनकूप्यूटर्स महिलाओं के नेतृत्व वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए न्यूलॉन 15 प्रतिशत सीटें आवंटित करेंगे।

5.10 क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

प्रत्येक वर्ष राज्य नोडल एजेंसी सरकारी अधिकारियों स्टार्टअप्स, इनकूप्यूटर्स, एजल निवेशकों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगी ताकि विश्वभर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की नव गतिविधि के बारे में जागरूक किया जा सके।

5.11 जिला नवाचार समिति:

उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अधीक्षता में एक जिला नवाचार समिति की स्थापना की जाएगी। जिसमें उद्योगों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और उद्योग निकायों के सदस्य शामिल होंगे। जिला नवाचार समिति अपने संबधित जिलों में स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगी और नवाचार और सद्व्यवहार की सरकृति को विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी।

इच्छुक स्टार्टअप उद्यमियों को मार्गदर्शन, हैंडहोल्डिंग सपोर्ट मैटरिंग सपोर्ट आदि प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला जिला उद्योग केंद्र स्टार्टअप हेल्प डेरक स्थापित करेगा और राज्य नोडल एजेंसी को इस कार्य के लिए नामित नोडल अधिकारी की सूचना देगा।

जिला नवाचार समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

(i) जिला रत्तर पर स्टार्टअप नीति का क्रियान्वयन।

(ii) उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में स्टार्टअप/उद्यमों के पोषण के लिए एक स्टार्टअप कार्य योजना प्रक्रिया और तंत्र तैयार करना।

(क) आकाशी स्टार्टअप उद्यमियों को सहायता प्रदान करना।

(ख) संबंधित जिलों से इनोवेटिव स्टार्टअप्स की पहचान करना।

(ग) इन्क्यूबेशन सेपोर्ट और मैटरिंग सेपोर्ट पाने के लिए उन्हें सहाय बनाना।

(घ) राज्य सरकार की एजेंसियों कॉरपोरेट्स आदि के माध्यम से संबंधित जिले में पायलट प्रोजेक्ट से गुजारने का अवसर प्रदान करना।

(छ) सार्वजनिक उपायन और संबंधित छुट्टों में वरीयता।

(च) निवेशकों, उद्यम पूजीपतियों आदि से धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

(छ) जिला नवाचार पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करना।

(ज) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधियाँ।

(ii) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता, सलाह और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट्स उद्योग संघों या पैशेवर संगठनों के साथ साझेदारी रखायित करना।

(iv) शासकीय कलीयरेंसेज अनुकूल आदि प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

(v) जिला रत्तर पर स्टार्टअप से सम्बन्धित विषयों या शिकायतों की पहचान के लिए तंत्र की स्थापना।

(vi) छात्रों महिलाओं आदि के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करना।

(vii) स्टार्टअप की बारीकियों पर सरकारी अधिकारियों उद्योग के सदस्यों मेन्टर्स और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।

5.12 जिला नवाचार कार्यक्रम

जागरूकता संपन्न करने और जमीनी नवाचारों और नवोदित स्टार्टअप उद्यमियों की पहचान करने के लिए, जिला नवाचार समिति केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जैसे कि:

(i) बी-प्लान प्रतियोगिताएं।

(ii) ग्राप्ट चैलेन्ज/आईडिया चैलेन्ज।

(iii) हैकथैन।

(iv) स्टार्टअप शोकेस दिवस/बीट्जी बीट।

(v) डेमो डे/ डिमांड डे आदि।

(vi) क्रेता-विक्रेता बैठकें।

उत्तराखण्ड के संबंधित जिलों में राज्य सरकार की एजेंसियों शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग निकायों, कॉर्पोरेट्स, वित्तीय संस्थानों आदि के सहयोग से।

5.13 बाजार में पहुंच के लिए कॉर्पोरेट इनोवेशन प्रोग्राम (सीआईपी):

उत्तराखण्ड में स्टार्टअप्स के लिए निजी क्षेत्र के बाजार में पहुंच के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से राज्य नोडल एजेंसी स्टार्टअप्स के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपोज़र की सुविधा के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित करेगी। राज्य सरकार सीआईपी के आयोजन के लिए अपेक्षित धन का प्रावधान करेगी।

5.14 नीति की समीक्षा:

राज्य सरकार दो वर्ष में एक बार इस नीति की समीक्षा करने के लिए एक संगिति का गठन करेगी, ताकि नीति की उपयोगिता, कार्यान्वयन में आसानी और प्राप्त परिणामों का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रतिवेदन को निर्णय के लिए उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउन्सिल के समक्ष रखा जाएगा।

5.15 इस नीति के अधीन प्रोत्साहन और लाभों की अनुमन्यता:

स्टार्टअप या इनक्यूबेटर, जो इस नीति के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं, नीति के समाप्त होने के पश्चात तीन वर्ष के भीतर नीति में प्रदत्त लाभों के लिए दावा करने के अहं होंगे।

आशा से,

लॉर्ड पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

Notification No. 371/VII-3-23/41-MSME/2016 Dated 17 March, 2023

Annexure

THE UTTARAKHAND
STARTUP POLICY, 2023
Promoting Innovations & Entrepreneurship

Table of Contents

BACKGROUND.....	434-435
OBJECTIVES.....	436
VISION	436
GOALS.....	436
VALIDITY OF THE POLICY	436
1. DEFINITION.....	436
1.1. Legal Entity (for the purpose of recognizing startups under this Policy)	436-437
1.2. Startups.....	437
1.3. Grassroot Innovation or Innovation/Startups with Rural Impact	437-438
1.4. Startups working on disruptive technologies	438-439
1.5. Startups by Women Entrepreneurs	439
1.6. Startups by Scheduled Caste or Scheduled Tribes or Differently Abled Person or by a Transgender.....	439
1.7. Startups by Student Entrepreneurs.....	439
1.8. Recognized Startup	439-440
1.9. Turnover.....	440
1.10. Stages of Startup	440
1.11. Innovation.....	440
1.12. Incubation Center or Incubator.....	440-441
1.13. Recognized Incubator.....	441-442
1.14. Lead Incubator.....	442
1.15. Mentors	442
1.16. Subject Matter Experts	442
1.17. State Government	442
1.18. State Government Agencies	442
1.19. Academic Institutions.....	443
1.20. Accelerator	443
1.21. Angel Network.....	443
1.22. Venture Capital.....	443
1.23. Uttarakhand Startup Council.....	443-444
1.24. State Nodal Agency	444

1.25. Uttarakhand Startup Cell	444
1.26. Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of Incentives - CoRDI	444
1.27. Limiting Clause	444
2. INCENTIVES FOR RECOGNIZED STARTUPS	445
2.1. Monthly Allowance	445
2.2. Seed Fund	445
2.3. Intellectual Property Rights	445-446
2.4. Incentives under MSME Policy	446
2.5. Pre-Incubation Support	447
2.6. Incubation Support	447
2.7. Provision of Land In Industrial Area / IT Parks / SEZ	447
2.8. National and International Exposure	447-448
2.9. Pilot Projects	448
2.10. Acceleration Program	448
2.11. Access to external funding	448
2.12. Ease of Doing Business	449
2.13. Public procurement	449-450
2.14. Access to Shared Facilities	450
2.15. Pro Bono Services	450
2.16. Skilled Human Resource	450
2.17. Resolution of Issues or grievances	450
2.18. Public consultations on the policies & schemes	450-451
3. INCENTIVES FOR INCUBATORS	452
3.1. Lead Incubator	452
3.2. Capital Grant for Incubation Centers	452
3.3. Operational Grant for Incubation Centers	452
3.4. Incubation Centers In Academic Institutions	453-454
4. PROMOTING ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA	454
4.1. Entrepreneurship Development Cells (eCells)	454
4.2. Student Startup Entrepreneurs	454
4.3. Syllabus on Entrepreneurship	454-455
4.4. Inclusion of Massive Open Online Course (MOOCs) In curriculum	455

4.5.	Training of trainers	455
4.6.	Faculties as Mentor of Startup	455
4.7.	Partnership between industry and academia	456
4.8.	Commercialization of Innovation in academic institutions ..	456
5.	GENERAL PROVISIONS	457
5.1.	Institutional Support	457
5.2.	Fab lab or Makers Lab or Prototyping lab	457
5.3.	Flagship Programs	457
5.4.	Sensitization Programs	458
5.5.	Funds of Funds or Venture Fund	458
5.6.	Establishment of Angel Network	458
5.7.	Activities to be undertaken by State Government Agencies	458-459
5.8.	Hackathons or Idea Challenge	459
5.9.	Encouraging Entrepreneurship among Women	459-460
5.10.	Capacity Building Programs	460
5.11.	District Innovation Committee	460-461
5.12.	District Innovation Programs	461
5.13.	Corporate Innovation Programs (CIPs) for Market Access:	461
5.14.	Review of the Policy	461
5.15.	Grant of incentives and benefits under this Policy	461

BACKGROUND

India is at the cusp of becoming the leading startup ecosystem in the world with a consistent annual growth of 12-15 per cent as estimated by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. India has more than 70,000 registered startups with at least 14,000 recognized during fiscal 2022, according to the Economic Survey 2021-22, around 8,900-9,300 of these are technology led startups, 1,300 new tech startups were born in 2021-22 alone implying there are 2-3 tech startups born every day. From producing its first unicorn startup in the year 2011 to hitting the century of unicorns in India in the year 2022, it has been a long and eventful journey for the Indian startup ecosystem. Funding raising and investments into startups has been at its peak globally. From the start of the year 2022 until July 2022, India has already seen 19 new unicorns. The total count of Indian tech startups that have entered the unicorn club to date stands at 105. With the increased funding activity and rise in valuations, the number of startups in the decacorn list is also on the rise across the country.

With proximity to national capital region (NCR), unique climatic condition coupled with natural flora and fauna, Uttarakhand can be considered as the strategic hub for the startups working in the sectors such as Food and Agriculture, Travel and Tourism, Education, Pharmaceutical, Wellness, Information Technology, Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, SaaS, Drone, Robotics etc. The state has conducive policies, business friendly environment, robust infrastructure which makes the state as most preferred startup destination in the country. The state is home to more than 700 startups by the end of June 2022, which was only 100 until end of the year 2018. Around thirteen (13) startups from the state have been successful in raising funds from notable angel investors, venture capital firms and other private investors by the end of the first quarter of 2022 as a result of focused efforts of Government of Uttarakhand. Till the mid of the year 2022, the state has been able to establish 55,000+ square feet of the incubation space in 11 incubation centers across the state, more than 190 registered mentors, 20+ angel investors and venture capitalist on-boarded along with on boarding of 13 partner organizations for providing technical and shared services to startups.

In the States' Startup Ranking 2019, Uttarakhand was recognized as the "Aspiring Leader" and "Regulatory champion". After the announcement of Uttarakhand Startup Policy and as a result of strategic programs and interventions undertaken, "Startup Uttarakhand" was recognized as "*An Institutional Champion*" and "*A Capacity Building Pioneer*". In the States' Startup Ranking 2021 announced by Startup India & DPIIT, Startup Uttarakhand was recognized as "*Leader*". The State Government has also formed CM Advisory group on Startups, Innovation and Entrepreneurship in the year 2020 to guide and advise Government of Uttarakhand on the strategic initiatives focused on Startups. Startup Uttarakhand has more than twenty (20) specially programs designed to guide, train, mentor and handhold aspiring entrepreneurs, incubators, investors, women entrepreneurs, government officials and

other ecosystem players from across the state. The state government organizes Startup Boot Camps, Grand Challenge, hackathons etc. to identify and recognize innovations ideas. The state also organizes national and international exposure visits for the stakeholders of the startups ecosystem.

It is evident from the current trends that startups have become the center of innovations across the world. They not only play important role in designing and developing innovative solutions to the complex problems but also plays vital role in improving employment patterns, providing job opportunities and wealth creation for the states. Startups boost the economy with revolutionary technology and create new industries over time. Countries that have provided suitable economic, political and social environments to startups have witnessed the positive impacts they have created for the country. Thus, to nurture the culture of innovation and entrepreneurship in the state of Uttarakhand, it is inevitable to support startups, incubators, investors, mentors and all other key stakeholders of the ecosystem with the futuristic policies, schemes and support systems. This demand the need to take strategic efforts and actions plans to further boost the startup ecosystem in the state.

In the wake of the drastic changes in the economic environment as result of pandemic across the world, it has become inevitable to design exemplary measures to support homegrown startup enterprises. As a result, it is important to revisit the State's Startup Policy and make sufficient provisions to support the further growth of startup ecosystem in Uttarakhand. Thus, with an objective to address the need of promoting innovations and entrepreneurship in solving the complex societal problems and to support key stakeholders of startup ecosystem, the "Uttarakhand Startup Policy 2023" has been brought in to force.

OBJECTIVES

The objective of this policy is to create the culture of innovation and entrepreneurship by establishing a robust startup ecosystem in the state. The growth of the startup ecosystem will be fueled with the establishment of world-class institutional infrastructure, incubation and mentoring network, enabling access to funds, providing market access, public procurement, business friendly and regulatory environment along with promotion of employment generation and wealth creation opportunities across the state.

VISION

To become a leading startup destination and develop Uttarakhand as the strategic startup hub for innovators, aspiring entrepreneurs, incubators and ecosystem players

GOALS

1. Stimulate the growth of 1000 startups including technology driven enterprises in next 5 years
2. Encourage the growth of startup enterprises working on innovative technologies, processes or procedures, eco-friendly technologies, social impact or sustainability having focus on solving complex problems and stimulating the growth of local economy through employment creation and wealth generation
3. Establish state of the art infrastructure and facilities for innovators, startups, aspiring students entrepreneurs, women entrepreneurs and other ecosystem stakeholders across the state
4. Establish 30 new incubation centers across the state with at least 1 incubation center in each district
5. Establish a mechanism to enable access to funds, key infrastructure and other key resources that are important for the growth of startup enterprises in the state
6. Enable collaborations between industry and academia to promote entrepreneurship, innovations and its commercialization and the growth of technology enterprises
7. Develop an environment conducive to the creation, growth or transformation of startups enterprises into a highly successful enterprises

VALIDITY OF THE POLICY

This Policy is valid for a period of 5 years from the date of its notification or until new Policy is formulated.

1. DEFINITION

1.1. Legal Entity (for the purpose of recognizing startups under this Policy)

A legal entity means a company incorporated in India as

- i. A private limited company as defined in the Companies Act 2013 or
- ii. A limited liability partnership firm under the provisions of Limited Liability Partnership Act, 2008 or

- ii. A partnership firm registered under section 59 of the Partnership Act, 1932

1.2. Startups

An entity shall be considered as a "Startup" under the Uttarakhand Startup Policy, 2023 if it fulfills the criteria as specified below:

For legal entities having Registered Office in Uttarakhand

- (i.) It should be a separate "Legal Entity" as defined in the sub-clause 1.1 of clause 1 and
- (ii.) The period of existence and operations of the legal entity should not exceed ten years from the date of its incorporation and
- (iii.) Turnover of the legal entity for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded one hundred crore rupees and
- (iv.) Entity should not have been formed by splitting up or reconstruction of an existing business and should not be a part of the family business or conglomeration and
- (v.) Entity should be working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation or
- (vi.) as per the criteria notified by Government of India from time to time for defining startups

Legal Entities having Registered Office in other states of India

In addition to the criteria define under sub clause 1.2 of this Policy:

- (i.) Entity shall have an office in Uttarakhand and should have significant operation of business from Uttarakhand
- (ii.) Entity shall be employ at least 70 percent of its overall full-time workforce (workforce shall include founder, cofounders, support staff, skilled staff working on company payroll) having a domicile of Uttarakhand during the entire period of recognition

1.3 Grassroot Innovation or Innovation/Startups with Rural Impact

Grassroot Innovations or Innovations/startups with rural impact shall be defined as

- (i.) creation or development or improvement of products or services that can solve the problems or challenges or issues faced by the people living in the rural or hilly region or

(ii.) the development or improvement of the product or services which is scalable and can generate wealth and provide livelihood opportunities to the people living in the rural or hilly region.

Startups, which are based in the regions as defined under category A and B of the Uttarakhand MSME Policy,2015 (as amended from time to time) and are working on some innovative means, ways or methods to solve the challenges, issues or problems faced by the people living in those region or providing livelihood opportunities to them shall be considered as Startups working towards grassroot innovations or innovations with rural impact.

1.4. Startups working on disruptive technologies

The qualification of startups working on disruptive technologies are as follows:

- (i.) **Startups working on futuristic technologies:** Startups that are working on futuristic technologies such as Neural Language Processing (NLP), Drones, Robotics, Defence, Aerospace, Space technologies, Fintech, Medtech, Healthtech to provide innovative solutions to the problem or challenges existing in the society or country.
- (ii.) **Startups working on Renewable energy:** Startups helping to reduce carbon footprints through a renewable and sustainable source of energy using clean technologies or solutions such as Solar energy, Wind energy, Hydro energy, Tidal energy, Geothermal energy, Biomass energy etc.
- (iii.) **Startups working on Climate Change:** Startups working in the area of eco-friendly and/or climate-friendly technologies/solutions that helps in reducing and offsetting carbon emissions or increasing the green cover in the region
- (iv.) **Startup working on Circular Economy:** Startups working in the four Rs of the circular economy namely;
 - (a.) Reuse: Cloth collection, circular fashion, second-hand products etc.
 - (b.) Recycle: Recycled plastic, bottles, construction with recyclable materials etc.
 - (c.) Reduce: Packaging with sustainable material, edible cutlery etc.
 - (d.) Remove: Urban farming, use of fossil fuel, carbon capturing etc.
- (v.) **Startup working on Sustainability:** A startup working on green and sustainable practices along with next generation cutting edge technologies, processes or solutions that are enabling the world at large to recover from years of overuse such as
 - (a.) improving the soil's health
 - (b.) protection of endangered species
 - (c.) protection of the ocean's biodiversity
 - (d.) clean technologies for alternative energy sources
 - (e.) clean technologies for water conservation and ground water recharging

- (f.) plantation and conservation of trees to increase green cover in particular region
- (g.) disaster management etc.

1.5. Startups by Women Entrepreneurs

Legal entity shall be considered as women startup wherein

- (i.) The entity is founded by a woman entrepreneur; and
- (ii.) the equity holding and, or partnership of the women founders in the legal entity is not less than 51 percent; and
- (iii.) woman is an active partner or director in the company and is actively looking after the day-to-day operations in the company

1.6. Startups by Scheduled Caste or Scheduled Tribes or Differently Abled Person or by a Transgender

The legal entity shall be considered as Startup by Scheduled Caste/Scheduled Tribes /Differently Abled/ Transgender wherein

- (i.) the entity is founded by a person from Scheduled Caste /Scheduled Tribes/Differently Abled/ Transgender; and
- (ii.) the equity holding and/or partnership by the person from Scheduled Caste ,Scheduled Tribes/Differently Abled/ Transgender is not be less than 51 percent in the legal entity so formed; and
- (iii.) is an active partner or director in the company and is actively looking after the day-to-day operations in the company

1.7. Startups by Student Entrepreneurs

Any person studying in

- (i.) schools, colleges, polytechnics, industrial training institutes (ITIs) or
- (ii.) any institution of higher education (HEIs), technical education, medical educations or ayush established by the state or central government or
- (iii.) skill training or vocational training institutes recognized by governments
- (iv.) any open university and/or university established through a State or Central Act or
- (v.) any other educational institution or university that is recognized by the State or Central Government

who is pursuing innovation (product, process, technology or business innovation)driven entrepreneurial ventures while studying with due permission from the respective board, institution and/or universities as the case may be

1.8. Recognized Startup

- (i.) Any legal entity fulfilling the criteria specified in sub-clause 1.2 of clause 1 and which is recognized as Startup by the Startup Task Force established

under the Uttarakhand Startup Policy shall be considered as recognized startups.

- (i) The startups ideas by student entrepreneurs, which are approved by the Startup Task Force established under the Uttarakhand Startup Policy shall be considered as a recognized startups.
- (ii) Entities that have been recognized as Startups under Uttarakhand Startup Policy 2018 shall be considered as recognized startup

1.9. Turnover

Turnover shall be as defined under the provision of The Companies Act, 2013

1.10. Stages of Startup

1.10.1. Ideation Stage

Idea Stage refers to an integral stage in the lifecycle of startup wherein feasibility analysis of the startup idea is performed to evaluate the success/failure of the concept.

1.10.2. Prototyping or Minimum Viable Product (MVP) Stage

Prototyping or MVP Stage refers to an integral stage in the lifecycle of a startup wherein the concept for the product or process or service is converted into the physical form and which can be produced and delivered in a limited capacity and can be scaled-up upon the success and requirement.

1.10.3. Scale-up Stage

Scale-up Stage refers to an integral stage in the lifecycle of a startup wherein company is ready with the validated/final product, process or services and is looking for its commercialization on a larger scale

1.11. Innovation

Inventions are the bedrock of innovation. An invention is a new solution to a technical problem that can be protected through patents.

Innovation means doing something new that improves the product, process or service. Innovation involves application of information, imagination and initiative in deriving greater or different values from resources. Innovations can be protected under intellectual property rights(IPRs).

1.12. Incubation Center or Incubator

An organization designed to support startup companies in the early stages to help them develop innovative products, processes or service with a scalable

business model through business support resources and facilities such as co-working space, prototyping labs and equipment for the development of products or services. The incubation center shall also provide access to hard and soft infrastructure, seed funding, business mentoring and coaching, shared services that shall including accounting, legal services, human resource, corporate connects, connect with industry mentor and investor, acceleration program and providing networking opportunities along with other support needed for the growth of the startups.

For the purpose of this policy, an incubation center shall be

- any entity funded or registered under the policies or schemes by the departments, agencies or bodies of Government of India such as Technology Business Incubator (TBI) under Department of Science & Technology, Atal Incubation Centre under NITI Aayog etc. or
- any existing incubation center established under the policies or schemes of any other state government in India which has its full functional facilities in Uttarakhand or
- any newly established legal entity registered in Uttarakhand for setting up of incubation center

which has its sole objective to promote innovation and entrepreneurship among the sections of the society.

1.12.1. For the purpose of this policy, an incubation center shall be a separate legal entity having the core objective to promote innovation and entrepreneurship across the state and which is registered under any one of the following categories:

- (i) A Society (under The Societies Registration Act, 1860) or
- (ii) A Section 8 Company (under The Companies Act, 2013) or
- (iii) A Private Limited Company (under The Companies Act, 2013) or
- (iv.) A Limited Liability Partnership (under The Limited Liability Partnership Act, 2008) or
- (v) A Public Charitable Trust (under The Indian Trusts Act, 1882)

1.13. Recognized Incubator

Any separate legal entity fulfilling the criteria as specified in sub-clause 1.11 of clause 1 and which is recognized as Incubator by the Uttarakhand Startup Council established under Uttarakhand Startup Policy shall be considered as recognized incubators.

Entities that have been recognized as Incubator under Uttarakhand Startup Policy 2018 shall be considered as recognized incubator.

1.14. Lead Incubator

The Government realizes that there is a need to create world-class incubation facilities in Uttarakhand with requisite physical infrastructure in terms of co-working space, prototyping labs with capital equipment and operating facilities. The incubation facility shall also provide product development and business-planning support, access to seed capital, subject matter experts, corporates, technology support providers, industry bodies, acceleration programs, trainings and capacity building programs along with other relevant components required for establishing innovation driven startup enterprises in the state.

While State Government will encourage establishment of Incubation Centers in all academic institutions and professional educational institutions across the state, the state shall also aim to establish a "Lead Incubator" to promote the culture of innovation and entrepreneurship in the state and to nurture innovative startup businesses in their pursuit to become scalable and sustainable enterprises. The "Lead Incubator" shall work as the Hub for the other recognized incubators (spokes) spread in the districts across the state.

1.15. Mentors

Mentor is a person with a proven track record who possess expertise in the area of his/her operations, possess specialize knowledge and carries real world practical experience to guide, mentor and train aspiring entrepreneurs

1.16. Subject Matter Experts

Subject Matter Expert is a certified professional who has domain expertise, specific skills or knowledge in specific sector and has vast practical experience working in his/her field.

1.17. State Government

For the purpose of this policy, State Government means Government of Uttarakhand

1.18. State Government Agencies

For the purpose of this policy, state government agencies shall include but not limited to the departments, institutions, agencies, authorities, boards or any other bodies including a society, trust, corporation set up under the act of the state legislature or established by Government of Uttarakhand and shall also include urban local bodies.

1.19. Academic Institutions

For the purpose of this policy, academic institutions shall include but not limited to,

- (i) schools, colleges, polytechnics, industrial training institutes (ITIs), or
- (ii) any institution of higher education (HEIs), technical education, medical education or ayush established by the state or central government; or
- (iii) skill training or vocational training institutes recognized by governments;
- (iv) any open university and/or university established by a State or Central Act; or
- (v) any other educational institution or university that is recognized by the State or Central Government

1.20. Accelerator

Accelerator is an organization or program that enables rapid growth of new Startups by providing specific services like: mentoring, training, resources and networking to help Startups increase their customer base, generate more profits, prepare for funding and professionalize their organization

1.21. Angel Network

An angel investor (also known as a private investor, seed investor or angel funder) is a high-net-worth individual who provides financial backing to early stage startups or entrepreneurs, typically in exchange of ownership in the form of equity in the company.

An angel network is a group of angel investors who pool their investments together, which is managed professionally for making investments in early stage startups.

1.22. Venture Capital

Venture Capital is a form of equity funding that is generally invested in startups with high growth potential upon critical appraisal of the project undertaken by venture capital firms. The capital is generally invested in return of equity shareholding

1.23. Uttarakhand Startup Council

The Uttarakhand Startup Council shall be the Governing Body comprising of members from Government of Uttarakhand, Incubation Centers, Industry Bodies, Academic Institutions, Corporates, Subject Matter Experts, Nationalized Banks, Financial Institutions, Venture Capital Firms or any other organization having vast experience working in National or International Startup Ecosystem

to advise State Government on the matters related to Startup Policy, Strategic Initiatives focused on promoting innovation and entrepreneurship across the state.

1.24. State Nodal Agency

Directorate of Industries, Department of MSME shall be the State Nodal Agency to fulfill the purpose set out in Uttarakhand Startup Policy 2023 and to look after the activities focused on the implementation of the provisions of Uttarakhand Startup Policy.

1.25. Uttarakhand Startup Cell

A startup cell will be established to take care of the day-to-day operations and activities to be carried out under the Uttarakhand Startup Policy. A dedicated startup Project Management Unit (PMU) adequately staffed with consultants from internationally reputed professional firms shall be on-boarded for supporting State Nodal Agency and Startup Cell.

1.26. Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of Incentives - CoRDI

The state nodal agency shall establish a Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of Incentives (CoRDI) comprising of members from department of State Government, Entrepreneurs, Investors, Banks, Financial Institutions, Academic Institutions, Industry Bodies, Subject Matter Experts, etc.

The Task Force or Committee shall take decisions related to:

- (a) Scrutiny and Assessment of the application received for startup recognitions and incentives
- (b) Grant of recognition or incentives to the entities which has applied for it
- (c) Any other decisions as may be notified by Uttarakhand Startup Council

1.27. Limiting Clause

1.27.1. The startups, incubators and nodal agencies recognized under Uttarakhand Startup policy 2018 shall be eligible to claim incentives only under the Uttarakhand Startup policy 2018 till the 21 February, 2025

1.27.2. Startups and incubators that have availed funding under "Uttarakhand Startup Policy 2018" shall not eligible to claim incentives for the same component under this new policy i.e. "Uttarakhand Startup Policy 2023" and

1.27.3. Startups and incubators that have availed funding under "Uttarakhand Startup Policy 2023" shall not eligible to claim incentives for the same components and/or categories under any other policies or schemes of Government of Uttarakhand

2. INCENTIVES FOR RECOGNIZED STARTUPS

FISCAL INCENTIVES

The fiscal incentives shall be granted in tranches to recognized startups only after proper assessment and evaluations of their startup idea, progress made by the startups since its inception and the requirement of funds submitted by them at the different stages of startups.

2.1. Monthly Allowance

Recognized startup or a startup by student entrepreneurs whose project is approved by the Task Force shall be eligible for a monthly allowance up to INR 15,000 per month per startup.

In case of a startup led by women entrepreneurs or by a person from Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Differently Abled, Transgender or a startups which is working towards grassroot innovations or innovations with rural impact or in any startup working on disruptive technologies shall be eligible for a monthly allowance up to INR 20,000 per month per startup.

The monthly allowances shall be a one-time assistance given to startups at the ideation stage for a maximum period of twelve (12) months.

2.2. Seed Fund

A recognized startup, which is at the ideation stage or prototyping or MVP stage shall become eligible for a one-time seed funding assistance up to INR 10 lakhs.

In case of startup led by women entrepreneurs or startup by a person from scheduled caste, scheduled tribes, differently abled, transgender or a startups that is working towards grassroot innovations or innovations with rural impact, seed funding assistance up to INR 12.5 lakhs.

An additional seed funding up to INR 2.5 lakhs shall be provided to startups working on disruptive technologies.

2.3. Intellectual Property Rights

All startups will be encouraged to avail incentives, benefits and/or support services for filing of IPR under the policies/schemes formulated by the departments of Government of India.

In other cases, startups can apply for incentives for filing IPR as specified below:

Patent

100 percent Reimbursement of the amount paid and maximum up to INR 10 lakh (per patent) for Indian Patent and up to INR 5.0 lakh (per patent) for International Patent can be sanctioned to each startup. Reimbursement will be before the expense paid towards Prior Art search, Government Filing Fees, Attorney Fees, Maintenance fees or any other legal fees for filing patent.

Reimbursement of expenses shall be made in two stages

- (i.) 75 percent after filing of patent application and
- (ii.) 25 percent at the time of grant of patent.

The support shall be for filing two working patents in the area in which the startup recognition is availed.

Trademark

Reimbursement up to INR 10,000 (per trademark) for filing trademark application. Reimbursement shall be for the expense paid towards Trademark Search, Government Filing Fees, Attorney Fees, Maintenance fees or any other legal fees for filing trademark application

The support shall be maximum for filing two trademark application in the name of the startup for which recognition is availed.

Industrial Design

Reimbursement up to Rs 10,000 (per industrial design) for filing Industrial Design application. Reimbursement shall be for the expense paid towards Government Filing Fees, Attorney Fees, Maintenance fees or any other legal fees for filing design application.

The support shall be maximum for filing two design application in the name of the startup for which recognition is availed.

2.4. Incentives under MSME Policy

Startups eligible under Uttarakhand MSME Policy or any other policies or schemes notified by the state government can avail incentive under the respective policies and/or schemes subjected to complying with the criteria and due procedure specified there under.

However, startups shall not be eligible to claim incentive for the same components and/or categories under any other policies or schemes of Government of Uttarakhand

2.5. Pre-incubation Support

Innovators or aspiring entrepreneurs or women/student entrepreneurs or startups with grassroot impact or innovator/entrepreneurs working in disruptive sector identified by the State Nodal Agency shall be eligible for a one-time free of cost incubation support to provide them mentoring support and handhold them for product development.

Pre-incubation program will be organized through reputed incubation centre or accelerators which shall be identified by State Nodal Agency from time to time. The pre-incubation support shall be a one-time support for a maximum period of four (4) months. The cost up to INR 10,000 per incubate shall be borne by the State Nodal Agency towards the pre-incubation program.

2.6. Incubation Support

All recognized startups shall be eligible for a one-time free of cost incubation support for a period of 12 Months in any recognized incubator subjected to the approval of State Nodal Agency.

Startups working on disruptive technologies shall be provided incubation support for additional 6 months.

The total cost to enroll in the incubation program for the recognized startups in the recognized incubator will be borne by State Government, which is specified in sub-clause 3.3 under clause 3.

2.7. Provision of Land in Industrial Area/ IT Parks/SEZ

The State Government shall make provision for allocation of land/space to recognized startups in notified industrial areas, IT Parks, special economic zones (SEZ) or any other state established or support industrial area at the base price.

2.8. National and International Exposure

Subjected to the approval of State Nodal Agency, recognized startups shall be eligible for financial assistance to participate in the reputed national or international, Trade Fairs, Exhibitions, Expositions, Conference, Seminar, Training Programs, Acceleration Programs etc.

Frequency of Assistance	Category of Participation	Assistance
One	International	<p>Reimbursement for the cost incurred towards</p> <ul style="list-style-type: none"> • traveling in economy class (for one founder/ cofounder) • budget
Two	National	<p>Accommodation (for one founder/ cofounder)</p> <ul style="list-style-type: none"> • stall space • participation fees, if any

2.9. Pilot Projects:

Recognized startups shall be eligible for one time assistance up to INR 3 lakhs for undergoing a pilot project for proof of concept, testing and market validation of the product or services with the State Government Agencies. An additional funding support up to INR 2.5 lakhs shall be provided to startups working on disruptive technologies.

The startup should have received letter of intent for undergoing a pilot project from the respective government agency.

2.10. Acceleration Program

The state government shall organize at least two acceleration program each year in partnership with venture capital firms or renowned accelerators or corporate house or any other recognized professional organization having specialization in designing and organizing acceleration program.

2.11. Access to external funding

In order to facilitate access to funding opportunities, the state government will establish a mechanism and/or a platform to provide an opportunity to eligible startups to mobilize funds at convenient terms (e.g. preferential lending, collateral-free lending, soft loans etc.) from external investors, banks, financial institutions, funding bodies, venture capitalists, investment networks etc.

NON-FISCAL INCENTIVES

2.12. Ease of Doing Business

Starting a business involves getting various departmental approval and clearances. Thus, it is very important that state government should work out a plan to minimize the regulatory compliances, punitive actions and provide support /awareness to these propellers of next stage economic growth.

The State Government shall enhance the ease of doing business by minimizing inspections and encouraging self- certifications. All recognized startups shall become eligible for exemption from inspection on self certification basis for a period of five years from the date of recognition under the following acts:

- (i) The Factories Act, 1948
- (ii) Shops and Establishment Act,
- (iii) The Maternity Benefit Act, 1961
- (iv) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act, 1970
- (v) The Payment of Wages Act, 1936
- (vi) The Minimum Wages Act, 1948
- (vii) The Employment Exchange Act, 1959
- (viii) Payment of Gratuity Act, 1972
- (ix) Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
- (x) Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
- (xi) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996
- (xii) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
- (xiii) The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952
- (xiv) The Employees' State Insurance Act, 1948
- (xv) Any other Acts, Rules, Regulations notified in this regard by the state or central government

The exemptions under the above Acts shall be subjected to the complying with the due procedure specified by Startup India, Department for Promotion of Industry and Internal Trade or by the concerned departments of state or central government or under the respective acts, rules or regulations.

2.13. Public procurement

All recognized startups shall become eligible for the exemption in public procurement as specified in Uttarakhand Purchase Preference Policy, Procurement Rules and amendments made there under. All State Government Agencies shall extend the exemptions specified under Uttarakhand Purchase Preference Policy and Procurement Rules (as amended from time to time) made there under to all recognized startups.

All State Government Agencies will be permitted to make direct procurement up to INR 10 lakhs exclusive of GST from recognized startups registered under Uttarakhand Purchase Preference Policy.

2.14. Access to Shared Facilities

The State Government will make arrangements to provide free access to the resources in the State Universities, Government Laboratories, Center of Excellence, Libraries or any other shared facilities which may be needed for the development of innovative idea/concepts and/or products and services by recognized startups.

2.15. Pro Bono Services

The State Government will establish partnerships with professional organizations, corporates, or with other organizations and service providers for providing training and mentoring such as Land D modules, tools and templates for investor pitch decks, etc. and handholding support such as accountancy, legal, human resource, cloud services etc. to facilitate and provide support to startups in development of products or services.

2.16. Skilled Human Resource

In order to support startups to recruit skilled and unskilled human resource, the State Government will establish a mechanism wherein the human resources can be recruited through polytechnics, industrial training institute, skill training and vocational training institutes, Uttarakhand Skill Development Mission, academic institutions etc

2.17. Resolution of issues or grievances

State Government will establish a unified web platform that will allow identification of issues or grievances of startups, incubators, investors, aspiring entrepreneurs and will establish a mechanism for the resolution of issues or grievances in a time bounded manner.

All State Government Agencies shall also establish an online mechanism for the identification and resolutions of issues or grievances of startups, incubators, investors, aspiring entrepreneurs and other ecosystem players, which are related to the respective agencies.

2.18. Public consultations on the policies & schemes

The state government will establish a mechanism to consult startups on the policies, schemes rules, regulations, government orders etc. made by the State

Government Agencies to take in to consider their suggestions while formulating them.

The startups working in the disruptive sectors such as GPS systems, Artificial Intelligence, Machine Learning, Cyber security, Blockchain, Big Data, Fintech, Transport, Urban mobility, eVehicle, Biotech, Healthcare, E-Pharmacy, Civil Aviation, Waste Recycling, Space Technologies, Drones, Robotics Tourism, Travel Tech, Renewable energy, Climate Change, Disaster Management, Medical Devices, Circular Economy, Sustainability etc. shall be consulted by the State Government Agencies while formulating policies, schemes rules, regulations, government orders etc. made for the startups respective sector.

3. INCENTIVES FOR INCUBATORS

3.1. Lead Incubator

The state government shall establish world-class incubation centers or Center of Excellences (CoEs) in the sectors such as manufacturing, transport, energy, health, education, agriculture, water and sanitation etc. in Uttarakhand. These objective of this incubation centers and/or CoEs shall be to encourage innovative technology based startups or startups that are solving grassroot challenges that have an application and/or impact in the core sectors of the economy.

3.2. Capital Grant for Incubation Centers

The state government will strive to establish state of the art incubation centers in partnership with Corporates, Nationally or Internationally recognized Professional organizations, Accelerators etc. on public private partnerships. The incubation centers approved and recognized by Uttarakhand Startup Council shall become eligible for a one time Capital Grant except the cost of land and building.

Descriptions	Quantum of Support	Extent of Assistance
Setting up of new incubation centers	up to INR 1 crore	maximum 50 percent of the amount proposed be spent
Expansion of existing incubation centers	up to INR 50 Lakhs	maximum 50 percent of the amount proposed be spent

The capital grant shall be disbursed on year on year basis subjected to the annual budget plan submitted by the applicant and approved by the Uttarakhand Startup Council. The applicant shall clearly define the business model for running the incubation center along with the annual budget plan submitted while making application and it shall become self-sustainable in a period of five years.

3.3. Operational Grant for Incubation Centers

Incubators recognized by Uttarakhand Startup Council shall become eligible for reimbursement up to Rs 1.00 Lakh per Startup to cover the cost of providing incubation support to startups as specified in sub-clause 2.6 of clause 2. An additional one-time assistance up to INR 5 lakhs can be provided to the recognized incubation centers subjected to the approval of the Uttarakhand Startup Council on case-to-case basis.

The recognized incubation centers shall be eligible for the operational grant once they have come in to operation and have started incubating startups recognized by council. The operation grant shall be for a maximum period of 5 years starting from the date on which written communicating is received by the State Nodal State from the incubation center of coming in to operation. Incubators shall physically incubate recognized startup at least for a period of 12 months and maximum for a period of 18 months.

The incubation center shall submit to the State Nodal Agency the quarterly report of the progress made by the incubated startups in the formats specified.

3.4. Incubation Centers in Academic Institutions

Universities, Institution of Higher Education, Technical Education, Medical Education, Polytechnics, colleges, schools etc. shall strive to set up a basic incubation facility along with prototyping labs and resources such as geographical resources, hard and soft infrastructural resources, process and pedagogy linked resources and sectoral systems within their campus.

Each incubation center shall also establish Student Innovation and Entrepreneurship Council (SIEC), employ human resources to look after the council, assign a senior competent authority for coordination of such a facility to develop action agendas for short and long term

Subject to the maximum cap specified in the below table, the fiscal support to academic institutions established by the State or Central Government will be up to 100 percent of the proposed budget and up to 50 percent of the proposed budget for the privately established academic institutions.

Fiscal Support	Universities	Institutions & Colleges	Polytechnic, ITIs, Schools etc.
Capital Grant for setting up of new incubation centers	Up to INR 1 Crore	Up to INR 30 lakhs	Up to INR 20 lakhs
Capital Grant for expansion of existing incubation centers	Up to INR 50 Lakhs	Up to INR 20 lakhs	Up to INR 10 lakhs

Operational grant	As specified in sub-clause 3.3 of clause 3	As specified in sub-clause 3.3 of clause 3	As specified in sub-clause 3.3 of clause 3
-------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------

4. PROMOTING ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA

4.1. Entrepreneurship Development Cells (eCells)

All academic institutions established by state government or under the Acts enacted by the state legislature shall establish Entrepreneurship Development Cells (eCells) and all privately established academic institutions will be encouraged to establish Entrepreneurship Development Cells (eCells) to create awareness and encourage students towards entrepreneurship within their campus. The academic institutions shall appoint a Startup Nodal Officer to look after the day to day operations of the eCells.

All eCells shall be affiliated with Startup Uttarakhand for organizing activities focused on entrepreneurship throughout the year. All eCells shall organize Startup boot camps, Business plan competitions, Startup pitch fest, Idea challenges, Grand challenge, Hackathons, etc., in association with Startup Uttarakhand, for the students who are willing to take up entrepreneurship.

eCells affiliated with Startup Uttarakhand shall be eligible for the financial assistance up to INR 100 lakhs per programs for meeting the expenses towards conducting programmes

4.2. Student Startup Entrepreneurs

Student entrepreneurs working on innovative startup ideas which is approved by the State Nodal Agency shall be eligible for pre-incubation support as specified in the sub-clause 2.5 of clause 2 and monthly allowance as specified in the sub-clause 2.1 of clause 2. The student entrepreneurs in the graduation and post-graduation will be permitted to convert their start-up project as their interim project or final year project required for the award of their degree.

Startup Uttarakhand will establish mechanism to facilitate student entrepreneurs for preliminary mentoring to do preliminary research for validation of idea, prototyping, MVP, field-testing, market research and filing IPR from time to time.

4.3. Syllabus on Entrepreneurship

All academic institutions shall formulate a Student Startup and Innovation Policy along with action plan and well defined short-term and long-term goals,

which should be in line with the Uttarakhand Startup Policy, 2023 and National Innovation and Startup Policy, 2019

Entrepreneurship promotion and development should be one of the major dimensions of the academic institution's strategy. The State Nodal Agency shall design and develop a curriculum focused on entrepreneurship development

All academic institutions shall update their curriculums to include the course on "Entrepreneurship Development" as an optional subject to make students aware and encourage them to take entrepreneurship as their carrier option.

All Academic Institutions shall also organize, at least one dedicated course focused on "Innovation and Entrepreneurship Development" for the identified students, in association with Uttarakhand Startup Cell as a part of the summer camp program.

4.4. Inclusion of Massive Open Online Course (MOOCs) in curriculum

Various nationally and internationally accredited Massive Open Online Courses focused on innovation and entrepreneurship or any other MOOCs designed and approved by the State Government will be made available on startup portal

These MOOCs may be taken by the aspiring student entrepreneurs as elective subjects and may be assigned to them depending upon their interest.

4.5. Training of trainers

Innovation and entrepreneurship can propel the youth towards breakthrough discoveries. The role of teachers, faculties and mentors becomes very important in guiding youth towards entrepreneurship. Strong emphasis will be put on training the teachers, faculties, government officials on the development in area of entrepreneurship by industry veterans, corporate and subject matter experts from startup ecosystem.

Financial assistance up to INR 1.00 lakhs per year per program per institution for organizing training and capacity programs focused on Startups for the resource person in academic institutions and state government agencies

4.6. Faculties as Mentor of Startup

Faculties in all academic institutions would be encouraged to take time off to work as a mentor with the aspiring students entrepreneurs at the incubator center or Entrepreneurship Development Cells (EDCs) for a stipulated time, after which they can join back to their normal work.

4.7. Partnership between industry and academia

Industry - Academia collaboration is vital for a sustainable ecosystem where both the industry and academia flourish. Partnerships with industry and corporates are very instrumental in advancing the research projects, catalyzing innovations and growth of technologies and for the creation of skilled workforce.

The state government will establish a mechanism to enable partnership between industry and academic institutions.

4.8. Commercialization of innovation in academic institutions

Cultivating the culture of innovation and entrepreneurial and providing timely support to start-ups, indeed, forms the rock-solid foundation for a progressive economy. Creating next-generation start-ups is the need of the hour. The research advances being made by academic institutions such as universities, schools, colleges, polytechnics, industrial training institute (ITIs), institutions of technical education, medical educations etc. can play a very important role in creation of next generation startups.

All academic institutions in Uttarakhand will be encouraged to provide access to research & development (R&D) projects, patented ideas or any other projects that has commercial value to aspiring student entrepreneurs, startups and member from industries with an objective to translate academic research discoveries into successful commercial ventures.

The aim is to benefit both research and business and to create new value as the new technology is put into use.

6. GENERAL PROVISIONS

5.1. Institutional Support

(i) Start-up Portal & Mobile App

The state government will upgrade the Uttarakhand Startup Portal and App as per the need to provide access to all information related to the startup policy, government notifications, applications for recognition and incentives etc. through Startup Portal.

(ii) Dedicated Helpline

A dedicated helpline to provide handholding support al. startup related queries will be established in English and Hindi. The helpline shall assist in addressing all queries in areas such as registering a business, raising funds/loans, policy clarifications, etc.

5.2. Fab Lab or Makers Lab or Prototyping Lab

A provision of funds shall be made for setting up of the fab lab, makers labs or common facility centers having modern facilities for product development, testing and validation, internet connectivity and other facilities required by innovators, startups, innovators. State Government will ensure establishment of at least two labs in the regions identified by State Nodal Agency.

5.3. Flagship Programs

To attract youth and motivate them to solve complex problems by taking up entrepreneurship, the State Nodal Department and the departments, agencies, bodies, corporations, urban local bodies, authorities and entities established by State Government shall

- (a) organize at least two national program such as Uttarakhand Innovation Week, Startup Tech fest, Startup Fundraising event, Uttarakhand Startup Conclave etc. in two different regions of Uttarakhand
- (b) organize district wise startup boot camps and at least one Idea Challenges, Grand Challenges, Rural Innovation Challenges, Hackathons etc. to seek out fresh ideas and projects from innovators from across the state
- (c) organize at least one program to provide market access to startups such as Uttarakhand Startup Exposition, Startup Product Showcase, Demo Day/Demand Day, B2G & B2B programs etc.

Annually, top twenty innovative startup ideas selected through a rigorous process during the challenges/competitions shall be provided seed fund of INR 2.0 lakhs which shall be in the form of grant in aid and incubation support along with publication of their success stories.

5.4. Sensitization Programs

In order to create awareness and create the culture of innovation and entrepreneurship across the state, the State Nodal Agency shall organize startup sensitization programs to guide, train and handhold aspiring entrepreneurs, incubators, investors, mentors, members from industry, professionals and other ecosystem enablers covering all the districts of the state.

5.5. Funds of Funds or Venture Fund

A fund of funds with a corpus of INR 200 crore shall be allocated for investing in venture funds that invest in startups with an objective to provide them scale up fund in the form of equity funding to enable them to develop and growth their enterprises. A professional fund manager shall be selected through open bidding process for the operation and management of the funds. A portion of the funds of funds can be used to setup the critical infrastructure in the lead incubator in the state.

The State Government Agencies can also establish sector specific venture fund from their budgets to invest in innovative and/or technology oriented startups in exchange of equity.

5.6. Establishment of Angel Network

The Government of Uttarakhand will sensitize industrialists, professionals, individual investors, high net-worth individuals (HNIs), non-resident Indian (NRIs), social impact investor groups' to establish Angels Network (Uttarakhand Angels) to enable an alternative source of early stage funding for startups operating from Uttarakhand.

5.7. Activities to be undertaken by State Government Agencies

All State Government Agencies shall

- (i) formulate startup policies which shall clearly define the annual plan for providing institutional support to startups in the form of sustainable programs, hackathons, grand challenges, incubation support, mentoring support, funding support, public procurement, venture funding, open data APIs and other sustainable programs
- (ii) establish startup help desk and appoint a nodal officer to look after its operation and management in order to provide them required guidance and handholding to aspiring startup entrepreneurs
- (iii) establish partnerships with corporates, industry associations or professional organizations to provide technical support, mentoring and other support to recognized startups
- (iv) organize training and capacity building programs for the government officials to guide, mentor and train them on the nuances of startups

- (v) establish an online mechanism for the identification of the issues or grievances related to it and addressal of the same in time bounded manner
- (vi) provide opportunities to recognized startups in the form of opportunity to undergo pilot project through grand challenges, idea challenge, demo day/demand day, innovation day etc to enable them to test and validate their product and services
- (vii) provide relaxation as specified in Uttarakhand Purchase Preference Policy, Procurement Rules to all recognized startups in all public procurements
- (viii) make a consultation with startups to take their suggestions on the changes to be made in the existing or in any new schemes, policies, rules, regulations, government orders etc. of the respective State Nodal Agencies in order to address the challenge faced by them
- (ix) enable hassle free and time-bounded statutory clearances to startups
- (x) organize annual programs as specified in sub-clause 5.2 of clause 5
- (xi) any other activities as may be specified by the state government from time to time

5.8. Hackathons or Idea Challenge

In order to find solutions to the complex problems, each year, the State Government Agencies shall identify a problem area or challenges from their respective sectors and invite all startups to develop innovative solutions to solve those problems.

The solutions so designed and developed by the startups and selected through a rigorous selection process shall be awarded an initial grant and may be taken up for implementation as a pilot project at an appropriate scale in the respective department, agencies, or bodies, corporations, authorities, urban local bodies or other entities.

The provision of funds for organizing the hackathon/idea challenge/innovation challenge and for giving an opportunity to the winning ideas to undergo pilot project shall be made by the respective State Government Agencies

5.9. Encouraging Entrepreneurship among Women

All State Government Agencies shall design and implement programs and initiatives in their respective areas to encourage women in entrepreneurship and establish a mechanism to guide, support and mentor women startups. At least two programs focused on women shall be organized in a year for their capacity building. The concerned Departments, agencies, bodies shall make a provision of funds for the same from their own budget.

All State Government supported incubators shall allocate minimum 15 percent seats for startups led by recognized startups led by women.

5.10. Capacity Building Programs

Every year, the State Nodal Agency shall organize capacity-building workshops for government official, startups, incubators, angel investors and other key stakeholders of startup ecosystem to sensitize over the recent developments in the startup ecosystem across the world

5.11. District Innovation Committee

A District Innovation Committee shall be established under the chairmanship of District Magistrate in each district of Uttarakhand involving members from Industries, Nationalized Banks, and Industry Bodies. The District Innovation Committee shall oversee the implementation of the startups policy in their respective districts and organize awareness programs to develop the culture of innovation and entrepreneurship.

Each district shall establish Startup Help Desk at the District Industries Center to provide guidance, handholding support, mentoring support etc. to aspiring startup entrepreneurs and shall notifying a nodal officer for the same to State Nodal Agency.

The district innovation committee shall look after

- (1) implementation of startup policy at the district level
- (2) prepare an startup action plan, processes and mechanisms for nurturing of Startups/enterprises in each district of Uttarakhand to
 - (a.) providing handholding support to aspiring startup entrepreneurs
 - (b.) identify innovative startups from the respective districts
 - (c.) enable them to get incubation support and mentoring support
 - (d.) provide an opportunity to undergo pilot project in the respective district through state government agencies, corporates etc.
 - (e.) preference in public procurement and related exemptions
 - (f.) facilitate to access funds from investors, venture capitalists etc.
 - (g.) organize programs focused on district innovation
 - (h.) any other activities specified by state government
- (3) establish partnerships with corporates, industry associations or professional organizations to provide technical support, mentoring and other support to recognized startups
- (4) simplify procedures and processes for getting the government clearances, licenses etc.
- (5) establishment of mechanism for identification of issues or grievance of startups at district level

- (6) organize programs in academic institutions to promote entrepreneurship among students, women etc.
- (7) organize sensitization programs for government officials, industry members, mentors and other ecosystem enables on the nuances of startups

5.12. District Innovation Programs

In order to create awareness and to identify grassroot innovations and budding startup entrepreneurs, the District Innovation Committee shall organize focused programs such as

- (i) B-plan competitions
- (ii) Grand challenges / idea challenge
- (iii) Hackathons
- (iv) Startup Showcase Days/B2G meets
- (v) Demo Day/Demand Day etc.
- (vi) Buyer-Seller Meets

in the respective districts of Uttarakhand in association with state government agencies, academic institutions, industry bodies, corporates, financial institutions etc.

5.13. Corporate Innovation Programs (CIPs) for Market Access:

With an aim to widen the scope of private sector market access for startups in Uttarakhand, State Nodal Agency will organize partnership-based programs with corporate to facilitate State, National and International level exposure to startups. The state government shall make provision of requisite funds for organizing CIPs.

5.14. Review of the Policy

State Government shall formulate a committee to review this policy once in two years to critically appraise the usefulness of the policy, the ease of implementation and the outcomes achieved. The report shall be placed before the Uttarakhand Startup council for its decision.

5.15. Grant of incentives and benefits under this Policy

Startups or incubators which are recognized under this Policy shall be eligible for claim the benefits under this for a period of three years after expiry of this Policy

By Order,

DR. PANKAJ KUMAR PANDEY,
Secretary



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुडकी, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1-क

गियम, कार्य-विधिगा, आकार. विज्ञप्तिपा इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल गहोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

March 03, 2023

No. 57/XIV/82/Admin.A/2003--Ms. Priti Sharma, 2nd Additional District Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 01.02.2023 to 10.02.2023 with permission to suffix 11.02.2023 & 12.02.2023 as second Saturday and Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

February 03, 2023
March

No. 58/XIV/9/Admin.A/2008--Shri Chandraman Rai, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 23.01.2023 to 01.02.2023 with permission to prefix 22.01.2023 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 03, 2023

No. 59/XIV-a-53/Admin A/2015--Ms Suman 8th Additional Civ Judge (Sr Div) Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 26 days w.e.f. 02.01.2023 to 27.01.2023.

NOTIFICATION

March 03, 2023

No. 60/XIV-79/Admin.A/2003--Ms Neelam Ratra 2nd Additional District & Sessions Judge Dehradun District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 16.01.2023 to 25.01.2023 with permission to prefix 14.01.2023 & 15.01.2023 as second Saturday and Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

March 03, 2023

No. 61/XIV-a-41/Admin.A/2008--Ms Kakkash Khan District & Sessions Judge, Champawat is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 18.11.2022 to 03.12.2022 with permission to suffix 04.12.2022 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge

Sd/-

I/c Registrar (Inspection)

कार्यालय सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

11 नवम्बर, 2022 ई०

पत्रांक-2799 / पंजीयन निरस्त / 2022-23 - वाहन संख्या UA033673 (HGV) मॉडल 2006 चैथिरा 42603.GVZ122763 इंजन नं 0 G0G62412067 इस कार्यालय अधिकारी खानुसार वाहन श्रीमती दीपा वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा निवासी-गोल्डी निवास निकट जो द्वी होटल टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/02/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने थोरा नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेंस से गुकत है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई वैक धालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का गूल चेचिस प्लॉट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। चक्षु लध्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) के न्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 11.11.2022 को वाहन संख्या UA033673 (HGV) मॉडल 2005 चैथिरा 42603.GVZ122763 इंजन नं 0 G0G62412067 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

21 दिसम्बर, 2022 ई०

पत्रांक -3007/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या LK03CA1386 (LGV) मॉडल 2018 चैचिस UK0418.02748 इंजन नं० 02748 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री विशन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी उचौलीगोठ टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है, दिनांक 14/12/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन थलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेंस से गुक्ता है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औपचित्य नहीं रहता है।

अतः रुरेन्द्र कुमार, सहायक राम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) के न्दीय मोटरवान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 21.12.2022 को वाहन संख्या UK03CA1386 (LGV) मॉडल 2018 चैचिस UK0418.02748 इंजन नं० 02748 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

23 दिसम्बर, 2022 ई०

पत्रांक:-3022/पंजीयन निरस्त/2022-23-वाहन संख्या UP291267 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 85VFJ38077P इंजन नं० B4387SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री कमल सिंह पुत्र श्री विजय रिंद निवासी-मकान संख्या 31 रिलाइ, शूष्मीदांग तहसील टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 12/12/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन थलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेंस से गुक्ता है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चैचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औपचित्य नहीं रहता है।

अतः रुरेन्द्र कुमार, सहायक राम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) के न्दीय मोटरवान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 23.12.2022 को वाहन संख्या UP291267 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 85VFJ38077P इंजन नं० B4387SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 दिसम्बर, 2022 ई0

पत्रांक 3073/पंजीयन निरस्त/2022-23 वाहन संख्या UK03ER0302 (E-RIKSHWA) मॉडल 2018 चैविस MAILP2FC3JSD7.033 मोटर नं 180.191953 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री रजवन्त सिंह महर पुत्र श्री यगा सिंह निवासी चचीलीगाँव, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 24/12/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेंस से भुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आव्याहन के अनुसार वाहन पर कोई वैक्यालान लम्बित नहीं है, सीनियर फौरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आव्याहानुसार वाहन का चैविस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/धिन्ह के बने रहने का कोई औपचित्य नहीं रहता है।

अत शुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) के न्दीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत पदात शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.12.2022 को वाहन संख्या UK03ER0302 (E-RIKSHWA) मॉडल 2018 चैविस MAILP2FC3JSD7.033 मोटर नं 180119 953 को उत्तराखण्ड पुलाव से भिरस्त करता हूँ।

शुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुक्तकी, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2023 ई0 (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन औंक इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन दादा, अशोक नगर, नई दिल्ली-110001

आदेश

दिनांक : 28 मार्च, 2023 ई0

संख्या 76/उत्तराखण्ड-विंस०/४९/२०२२/सी०ई०८०८०-३३-यत, उत्तराखण्ड राज्य की ४९-सल्ट विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन २०२२ अधिसूचना नं ४६४/उत्तराखण्ड-विंस०/२०२२ दिनांक २१.०१.२०२२ के जरिए की गई थी।

यहाँ सौक प्रनिविधित अधिनियम, १९५१ की धारा ७८ के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित धर्मधर्म के निर्वाचन की तारीख में ३० दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है और

यतः ४९-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम १० मार्च, २०२२ को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख ०९ अप्रैल, २०२२ थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पञ्च सं २७८२/XXV ५३/२०२२ वेस्टग्राउन के जरिए अप्रेषित दिनांक २२/०४/२०२२ की रिपोर्ट के अनुसार श्री भौले शंकर आर्या (एडवोकेट) जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन २०२२ के निर्वाचन क्षेत्र ४९-सल्ट से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं विश्वे द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विभावन नहीं है, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बल्मोहा, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उत्तर रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का सचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के असर्गत निर्वाचन व्यव प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शोले शंकर आर्या (एडब्ल्यूकेट) को कारण बताओ नोटिस सं 76/उत्तराखण्ड-वि स/49/2022/सी ई एम एस II, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था, और

यतः, निर्वाचनों का सचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शोले शंकर आर्या (एडब्ल्यूकेट) को निवेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर सेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, लिखित रूप में अपना अस्थायेदग प्रस्तुत करें और माथ ही निर्वाचन व्यव का अपना सेखा दाखिल करें, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी बल्मोहा द्वारा अपने दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यव सेखा (वि0स0सा0नि0-2022) के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उत्तर नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बल्मोहा द्वारा दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यव सेखा (वि0स0सा0नि0-2022) के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 में यह यताया गया है कि श्री शोले शंकर आर्या (एडब्ल्यूकेट) ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यव का सेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का समाकृ नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न भी कोई कारण बनाया है और न ही कोई अपूर्णकरण विद्या है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शोले शंकर आर्या (एडब्ल्यूकेट) निर्वाचन व्यवों का सेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अधिकारी और विधायिका नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-
"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्यवों का सेखा उस समय के भीतर लौर उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अनेकांश है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अज्ञान कारण या अव्याप्तिकार्य नहीं गवाता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रबन्धित आदेश द्वारा उभको निर्वाचन घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचन घोषित होगा।

यतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एवं द्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2022 में निर्वाचन नहीं करने वाले अभ्यर्थी श्री शोले शंकर आर्या (एडब्ल्यूकेट) निवासी मुक्त श्री साधो राम आर्या, ग्राम-नैकणा, पोस्ट ऑफिस-पैसिया, तहसील-सल्ट, जिला-बल्मोहा, जो इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अधिकारी राज्य अधिकारी संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निर्वाचन घोषित हैं।

ORDER

March 23, 2023

No. 76/Uttarakhand-LA/49/2022/CEMS- III--WHEREAS, the General Election to 49-Salt Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464 Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from, the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 49-Salt Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of election expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Almora, Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22nd April, 2021, Sh. Bhale Shankar Arya (Advocate), a contesting candidate of Uttarakhand from 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Almora, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand, a Show-Cause notice, 76/ Uttarakhand -LA /2022/49/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Bhale Shankar Arya (Advocate) for not lodging the account of election expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, Sh. Bhale Shankar Arya (Advocate) was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 17.1.2022. The acknowledgement receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Almora, vide its letter No. पत्र संख्या ४४/२९-लियोचन व्यव सेवा (विभागीय-०-२०२२) dated 16.02.2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Almora in his Supplementary Report dated 15.02.2023 vide its letter No. 16.02.2023 के पत्र संख्या ४४/२९-लियोचन व्यव सेवा (विभागीय-०-२०२२) has reported that Sh. Bhale Shankar Arya (Advocate) has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Bhole Shankar Arya (Advocate) has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure.

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Bhole Shankar Arya (Advocate) resident of S/O Sadhu Ram Arya, Village- Nalkana, Post Office- Padya, Tehsil- Salt, District- Almora, a contesting candidate from 49-Salt Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

आदेश

दिनांक : 23 मार्च, 2023 ई०

संख्या 78/उत्तराखण्ड-प्रियोग/49/2022/सी0ई0एम0एस0-III-यत, उत्तराखण्ड राज्य की 49-सल्ट विधान सभा क्षेत्र के राजाराजन निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं 484/ उत्तराखण्ड-प्रियोग/2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी

यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की आगा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अधिकारी को, निर्वाचित अधिकारी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यव के अपने लेखे की मही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है और

यह 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10प्रैर्याद 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यव का लेखा दाखिल करने की अनिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी, और

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और सुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं 2782/XXV-53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेशित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री ललित मोहन सिंह जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 49-सल्ट से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेशित रीति से अपने निर्वाचित व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचितों का सचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री ललित मोहन सिंह को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.स/49/2022/मी ई० एस एस -।।, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचितों का भाचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कागण बताओ नोटिस के जरिए श्री ललित मोहन सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि०स०सा०नि०-2022) के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के चाचा द्वारा दिनांक 29.11.2022 से प्राप्त किया गया था; और,

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि०स०सा०नि०-2022) के जरिए भेजी गई अनुपूरक संबोधा रिपोर्ट दिनांक 16.02.2023 में यह बताया गया है कि श्री ललित मोहन सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का भग्यकृ नोटिस भिजने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न हो कर्द जारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का मह समाधान ही गया है कि श्री ललित मोहन सिंह निर्वाचन खत्तों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अवधारणा और विवरण नहीं है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुवंशित किया गया है कि -

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान ही जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्यर्थों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आवेदन द्वारा उसको निर्भीत घोषित करेगा और तेस व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्भीत होगा;

यतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुभव में भारत निर्वाचन आयोग एवं द्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन धेन से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री ललित मोहन सिंह निवासी पुन श्री हृषि सिंह, ग्राम-उदयपुर, पोस्ट ऑफिस- उदयपुर, तहसील- स्थाल्दे, जिला-अल्मोड़ा को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अवधारणा गत्य अवधारणा संघ राज्य सेत्र की विधान सभा अवधारणा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अवधारणा होने के लिए निर्भीत है।

ORDER

March 23, 2023

No. 76/Uttarakhand-LA/49/2022/CEMS- III--WHEREAS, the General Election to 49-Salt Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand LA/2022 dated 21st January, 2022

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 49-Salt Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Almora, Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22nd April, 2021 Sh. Lalit Mohan Singh, a contesting candidate of Uttarakhand from 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Almora, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand, a Show-Cause notice, 76/ Uttarakhand -LA/2022/49/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Lalit Mohan Singh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, Sh. Lalit Mohan Singh, was directed to submit his representation in writing within explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 30 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's Uncle on 29.11.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Almora, vide its letter No. पत्र संख्या ४४/२९-लियोग्यता दस्तावेज (विभागीय) dated 6.02.2023, and

WHEREAS, the District Election Officer, Almora in his Supplementary Report dated 15.02.2023 forward vide its letter No. 16.02.2023 के पत्र संख्या ४४/२९-लियोग्यता दस्तावेज (विभागीय) (विभा०-२०२२) has reported that Sh. Lalit Mohan Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Lalit Mohan Singh, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that -

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Lalit Mohan Singh resident of S/O Mr. Harsh Singh Manral, Village- Udaypur, Post Office- Udaypur, Tehsil- Syalde, District- Almora, a contesting candidate from 49-Salt Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

आदेश

दिनांक : 23 मार्च, 2023 ई०

संख्या 76/उत्तराखण्ड-विभाग/49/2022/सी0ई0एम0एस0-III-यत् उत्तराखण्ड राज्य की 49-सल्ट विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं 464/ उत्तराखण्ड-विभाग/2022 दिनांक 21.01.2022 जारी की गई थी।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है और

यत् 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अनिम सारीख 08 अप्रैल, 2022 थी; और

યતઃ, જિલા નિર્વાચન અધિકારી અલ્મોડા, ઉત્તરાખણ્ડ કે દ્વારા પ્રસ્તુત ઔર મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી, ઉત્તરાખણ્ડ દ્વારા પત્ર સં 2782/XXV 53/2022 દેસ્સગ્રદુન વે જરિએ અગ્રેષિત દિનાંક 22/04/2022 કે રિપોર્ટ કે અનુસાર શ્રી રાકેશ નાથ જા ઉત્તરાખણ્ડ વિધાન સભા કા સાધારણ નિર્વાચન 2022 કે નિર્વાચન શેન્ચ 49-સલ્ટ સે લઙ્ઘને બાલે અભ્યર્થી હું વિધિ દ્વારા યથાપેશીત રીતિ સે અપને નિર્વાચન વ્યય કા કોઈ ભી લેખા દાખિલ કરને મેં વિફળ રહે હું, ઔર,

યતઃ, જિલા નિર્વાચન અધિકારી, અલ્મોડા, ઉત્તરાખણ્ડ ઔર મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી, ઉત્તરાખણ્ડ કી ઉત્ત રિપોર્ટોર્ટો કે આધાર પર ભાગ્ત નિર્વાચન આયોગ દ્વારા નિર્વાચનો કા સંચાલન નિયમ 1961 કે નિયમ 89 કે ઉપ નિયમ (5) કે અંતર્ગત નિર્વાચન વ્યય પ્રસ્તુત નહીં કરને કે લિએ શ્રી રાકેશ નાથ કો કારણ બતાઓ નોટિસ સં. 76/ઉત્તરાખણ્ડ વિ સ /49/2022/એ ઈ એમ એસ -ના, દિનાંક 20 અક્ટૂબર, 2022 જારી કરાયા ગયા થા; ઔર

યતઃ, નિર્વાચનો કા સંચાલન નિયમ 1961 કે નિયમ 89 કે ઉપ-નિયમ (6) કે અનુસાર, દિનાંક 20અક્ટૂબર, 2022 કે ઉપર્યુત્ત કારણ બતાઓ નોટિસ કે જરિએ શ્રી રાકેશ નાથ કો નિદેશ દિયા ગયા થા કિ બે ઇસ નોટિસ કે પ્રાપ્ત હોને કે 20 દિનોને કે અંદર લેખા ન પ્રસ્તુત કર પાતે કે કારણોનો કો સ્પષ્ટ કરતે હુએ લિખિત રૂપ મેં અપના અભ્યાવેદન પ્રસ્તુત કરે ઔર માથ હી, નિર્વાચન વ્યય કા અપના લેખા દાખિલ કરે; ઔર

યતઃ, જિલા નિર્વાચન અધિકારી, અલ્મોડા દ્વારા અપને દિનાંક 16.02.2023 કે પત્ર સંખ્યા 88/29-નિર્વાચન વ્યય લેખા (વિ0સ0સા0નિ0-2022) કે જરિએ આયોગ કો સૂચના દી ગઈ બી ઉત્ત નોટિસ અભ્યર્થી દ્વારા દિનાંક 28.11.2022 કો પ્રાપ્ત કરાયા ગયા થા; ઔર,

યતઃ, જિલા નિર્વાચન અધિકારી, અલ્મોડા દ્વારા દિનાંક 16.02.2023 કે પત્ર સંખ્યા 88/29-નિર્વાચન વ્યય લેખા (વિ0સ0સા0નિ0-2022) કે જરિએ પ્રસ્તુત બી ગઈ અનુપૂરક સર્વીશા રિપોર્ટ દિનાંક 15.02.2023 મેં યહ બતાયા ગયા હૈ કિ શ્રી રાકેશ નાથ મેન તો કોઈ ભી અભ્યાવેદન ઔર ન હી અપને નિર્વાચન વ્યય કા લેખા દાખિલ કરાયા હૈ। ઇસેને અતિરિક્ત ઉન્હોને ભારત નિર્વાચન આયોગ કા મમ્યક નોટિસ મિલને કે ઉપરાંત ભી ઉત્ત વિફળતા કે લિએ ન તો કોઈ કારણ બતાયા હૈ ઔર ન હી કોઈ સ્પષ્ટીકરણ દિયા હૈ; ઔર,

યતઃ, આયોગ કા યાદુ સમાધાન હો ગયા હૈ કિ શ્રી રાકેશ નાથ નિર્વાચન વ્યાચીનો કા લેખા દાખિલ કરને મેં વિફળ રહે હું ઔર ડનેકે પાસ ઇસ વિફળતા કે લિએ કોઈ ભી ઉચ્ચિત કારણ અથવા શ્રીચિત્ય નહીં હૈ; ઔર

યતઃ, લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 કી ધારા 10ક મેં અનુબંધિત કરાયા ગયા હૈ કિ .

"યદિ નિર્વાચન આયોગ કા સમાધાન હો જાતા હૈ કિ કોઈ વ્યક્તિ .

(અ) નિર્વાચન વ્યયોનો કા લેખા ઉત્ત સમય કે ભીતર ઔર ઉત્ત રીતિ મેં બેસી ઇસ અધિનિયમ કે દ્વારા યા અધીન અપેક્ષિત હૈ, દાખિલ કરને મેં અસફળ રહા હૈ; તથા

(બ્ય) ઉત્ત અસફળતા કે લિએ કોઈ અન્ય કારણ યા ન્યાયોચિત્ય નહીં રહ્યાના હૈ, તો નિર્વાચન આયોગ શાસકીય રાજ્યપત્ર મેં પ્રકાશિત આદેશ દ્વારા ઉત્તસ્કો નિરહિત ધોયિત કરેના ઔર એસા ધ્યાનિક ઉત્ત આદેશ કી તારીખ સે તીન વર્ષ કી કાલાવણી કે લિએ નિરહિત હોયા;

યતઃ, અવ લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 કી ધારા 10ક કે અનુસરણ મેં ભારત નિર્વાચન આયોગ એતદ્વારા ધોયણા કરતા હૈ કિ ઉત્તરાખણ્ડ રાજ્ય કે 49-સલ્ટ વિધાન સભા નિર્વાચન શેન્ચ મેં ઉત્તરાખણ્ડ રાજ્ય મેં વિધાન સભા કે સાધારણ નિર્વાચન, 2022 મેં નિર્વાચન લઙ્ઘને બાલે અભ્યર્થી શ્રી રાકેશ નાથ નિર્વાચન આયોગ પાન સ્થિત, ગ્રામ-ગગોડા, પોસ્ટ ગોફિસ- ડમરા, રહસીલ- ભિકિયાસીણ, જિલા-અલ્મોડાના કો ઇસ આદેશ કી તારીખ ને તીન વર્ષ કી અવધિ કે લિએ મસાદ કે કિંમી ભી મદદ અથવા રાજ્ય અથવા મંદ રાજ્ય કી વિધાન સભા અથવા વિધાન પરિષદ કા સદભ્ય ચુને જાને અથવા હોને કે લિએ નિરહિત હૈ

ORDER

March 23, 2023

No. 76/Uttarakhand-LA/49/2022/CEMS- III--WHEREAS, the General Election to 49-Salt Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of his account of expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 49-Salt Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Almora, Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22nd April, 2021, Sh. Rakesh Nath, a contesting candidate of Uttarakhand from 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Almora, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand, a Show-Cause notice, 76/ Uttarakhand -LA/2022/49/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Rakesh Nath, for not lodging the account of Election Expenses, and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, Sh. Rakesh Nath, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 28.1.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Almora, vide its letter No. पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यवस्था (विभागीय नियम) 2022 dated 16.02.2023, and,

WHEREAS, the District Election Officer, Almora, in his Supplementary Report dated 15.02.2023 forward vide its letter No. 6.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यवस्था (विभागीय नियम) 2022 has reported that Sh. Rakesh Nath, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Rakesh Nath has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Rakesh Nath resident of S/O Paan Singh, Village-Gangaur, Post Office- Dabharu, Tehsil- Bhikiyasain, District- Almora, a contesting candidate from 49-Salt Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order

आदेश

दिनांक : 23 मार्च, 2023 ई०

संख्या 76/उत्तराखण्ड-विरोद्ध/53/2022/सीई०एम०एस०-III-यत, उत्तराखण्ड राज्य की 53-जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना न. 484/उत्तरा०-विरोद्ध/2022 दिनांक 21.01.2022 को जारी की गई थी।

यहांलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की, निर्वाचन अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है, और

यत् 53-जागेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्विग्रह अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी, और

यह, जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं 2782/XXV-53/2022 देहनावून के जरिए अयोग्य दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मनीष सिंह नेही, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 53-जागेश्वर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं विधि द्वारा व्यापेक्षित गीनि से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचिनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मनीष सिंह नेगी, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि. स./53/2022/सी.ई.एम.एस.ना।, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचिनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (8) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए, श्री मनीष सिंह नेगी, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त स्तोत्रों के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने दिनांक 28.02.2023 के पत्र संख्या 110/29-निर्वाचन व्यय लेखा/2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 16.02.2023 के पत्र संख्या 88/29-निर्वाचन व्यय लेखा (वि०स०ता०नि०-२०२२) के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संबीक्षा रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 में यह बताया गया है कि श्री मनीष सिंह नेगी, ने न तो कोई श्री अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनीष सिंह नेगी, निर्वाचन खबरों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस ममत के भीतर और उग रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित नहीं रहता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से दीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

यतः, अब नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतहारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 53-जागेश्वर विधान सभा निर्वाचन थेट्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मनीष सिंह नेगी, निवासी एन० ०९, चक पनुवानौला, पो०- पनुवानौला, तहसील- भनोली, जिला-अल्मोड़ा। को इस आदेश की तारीख से दीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-थेट्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
प्रताप सिंह शाह,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ORDER

March 23, 2023

No. 76/Uttarakhand-LA/63/2022/CEMS- III--WHEREAS, the General Election to 53-Jageshwar Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 53-Jageshwar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Almora, Uttarakhand and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22nd April, 2021, Sh. Manish Singh Negi, a contesting candidate of Uttarakhand from 53-Jageshwar Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Almora, Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand, a Show-Cause notice, 76/ Uttarakhand -LA /2022/53/CLMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Manish Singh Negi, for not lodging the account of election expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, Sh. Manish Singh Negi, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 26.11.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Almora, vide its letter No. 110/29- दस्य लेखा/2023 dated 28.02.2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Almora, in his Supplementary DEO's Scrutiny Report date 15.02.2023 vide its letter No. 16.02.2023 के पर संख्या ४४/२९-टिर्फ्टचन दस्य लेखा (विभागीय समिति-2022) has reported that Sh. Manish Singh Negi, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Manish Singh Negi has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure.

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and *any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order*";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Manish Singh Negi resident of H.N. 09, Chek Panuwanaula, P.O- Panuwanaula, Tehsil- Bhanoli, District- Almora, a contesting candidate from 53-Jageshwar Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

By Order,
PRATAP SINGH SHAH,
Joint Chief Electoral Officer,
Uttarakhand.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुडकी, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2023 ई० (चैत्र 18, 1945 शक सम्वत)

भाग ४

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम स. यावर अली S-YAVARALI की जगह बदल कर सैय्यद यावर अली SYED YAVARALI रखा लिया है। भविष्य में मुझे सैय्यद यावर अली के नाम से ही जाना पहचाना जाये।

समर्त विधिक आपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सैय्यद यावर अली पुत्र शबी हैदर ज़ैदी
निवासी मोहल्ला किला, कस्ता बंगलौर
जिला हरिहार।

पी०एस०य०० (आर०ई०) 14 हिन्दी गजट/148-माण ४-2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवं प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी।